



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 17, 2009/फाल्गुन 26, 1930

No. 35]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 17, 2009/PHALGUNA 26, 1930

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2009

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन

(पांचवां संशोधन) विनियम, 2009

(2009 का संख्यांक 4)

फा.सं. 3-21/2009-बीएंडसीएस.—भारत सरकार, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) की अधिसूचना सं. 39 जो,—

(क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (ट) के परंतुक तथा धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थी, तथा

(ख) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III खंड 4 में दिनांक 9 जनवरी, 2004 की अधिसूचना संख्या का.आ. 44(अ) और 45(अ) के तहत प्रकाशित हुई थी,

के साथ पठित भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii), (iv) और (v) और धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 (2004 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान विनियम कहा गया है) में,—

(क) उप-खंड (i) को उप-खंड (ix) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ख) उप-खंड (i) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“(क) “कैरिज शुल्क” से अभिप्रेत है किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के किसी वितरक को, अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में प्रसारक के विभिन्न चैनलों के स्थापन को विनिर्दिष्ट किए बिना, टीवी चैनलों के ऐसे वितरक द्वारा स्वामित्व किए अथवा प्रचालित वितरण प्लेटफार्म पर उस प्रसारक के चैनलों अथवा चैनलों के बुके के कैरिज के लिए संदत्त किया गया कोई शुल्क;”

(ग) उप-खंड (ठ) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“(ठक) “इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा” से अभिप्रेत है एक या अधिक सेवा प्रदाताओं के क्लोजड नेटवर्क पर इंटरनेट प्रोटोकॉल का प्रयोग करके एड्रेसेबल मोड में मल्टी चैनल टीवी कार्यक्रमों का वितरण;

(घ) उप-खंड (डग) को उप-खंड (डघ) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया जाएगा;

(ड.) उप-खंड (डख) के पश्चात, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“(डग) “स्थापन शुल्क” से अभिप्रेत है किसी प्रसारक द्वारा टीवी चैनलों के किसी वितरक को, टीवी चैनलों के ऐसे वितरक द्वारा स्वामित्व किए अथवा प्रचालित वितरण प्लेटफार्म पर अन्य प्रसारकों के चैनलों अथवा बुके की तुलना में प्रसारक के चैनलों अथवा चैनलों के बुके के स्थापन के लिए संदत्त कोई शुल्क;”

3. प्रधान विनियमों के विनियम 3 में,—

(क) उप-विनियम 3.2 के द्वितीय परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“परंतु यह भी कि इस उप-विनियम के उपबंध टीवी चैनलों के ऐसे वितरक के मामले में लागू नहीं होंगे जो किसी प्रसारक से किसी विशेष टीवी चैनल के सिगनल प्राप्त करता है, और उसके साथ ही अपने वितरण प्लेटफार्म पर उस चैनल को कैरी करने के लिए कैरिज शुल्क की मांग भी करता है।”

(ख) उप-विनियम 3.2 में इस प्रकार अंतःस्थापित तीसरे परंतुक के पश्चात, स्पष्टीकरण को स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा,

(ग) इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थातः—

“स्पष्टीकरण 2. अनुरोधित चैनल(लों) के सिगनल उपलब्ध कराने के लिए एक “पूर्व-शर्त” के रूप में ऐसे प्रसारक द्वारा, जिससे टीवी चैनलों के किसी वितरक द्वारा सिगनल प्राप्त किए गए हैं, “प्लेसमेंट प्रीक्वेंसी” अथवा “पैकेज/टियर” के अनुबंध के फलस्वरूप भी अयुक्तियुक्त निबंधनों का अधिरोपण होगा।”

4. प्रधान विनियमों के विनियम 4 में,—

(क) उप-विनियम 4.1 के प्रथम परंतुक में, "करार, लिखित अथवा मौखिक" शब्दों के स्थान पर "लिखित करार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-विनियम 4.1 के द्वितीय परंतुक में, "करार, लिखित अथवा मौखिक" शब्दों के स्थान पर "लिखित करार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

5. प्रधान विनियमों में, विनियम 4 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किए जाएंगे अर्थात्:—

"4क. अंतरसंयोजन करार लिखित में किए जाएंगे.

4क.1 पे-चैनलों के प्रसारकों तथा टीवी चैनलों के वितरकों के लिए उनके सभी अंतरसंयोजन करारों के निबंधन और शर्तों को लिखित में समांतरित करना अनिवार्य होगा।

4क.2 पे-चैनलों का कोई प्रसारक अथवा टीवी चैनलों का कोई भी वितरक, जैसे मल्टी सिस्टम प्रचालक अथवा हैडएंड-इन-द-स्काई प्रचालक, एक लिखित अंतरसंयोजन करार किए बिना टीवी चैनलों के किसी भी वितरक को टीवी सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएगा।

4क.3 किसी न्यायालय अथवा अधिकरण के किसी आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय, जिसमें ऐसे न्यायालय अथवा अधिकरण के समक्ष किसी लंबित किसी कार्यवाही पर कोई आदेश अथवा निदेश अथवा निर्णय भी शामिल है, के अनुसरण में अथवा अनुपालन में विनियम 4क.1 अथवा 4क.2 में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी प्रसारक अथवा टीवी चैनलों के वितरक, जैसे मल्टी-सिस्टम प्रचालक अथवा हैड-एंड-इन-द-स्काई प्रचालक द्वारा सिग्नलों की किसी आपूर्ति अथवा टीवी चैनलों के सिग्नलों की आपूर्ति को जारी रखने पर लागू नहीं होगी।

4क.4 पे-चैनलों के प्रत्येक प्रसारक, जो टीवी चैनलों के वितरक के साथ अंतरसंयोजन करार करता है, का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह करार निष्पादित किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर टीवी चैनलों के ऐसे वितरक को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति सौंपे और इस संबंध में एक पावती प्राप्त करे, तथा इसी प्रकार, यथास्थिति, प्रत्येक मल्टी सिस्टम प्रचालक अथवा हैडएंड-इन-द-स्काई प्रचालक, जो किसी केबल प्रचालक के साथ अंतरसंयोजन करार करता है, का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह करार निष्पादित किए जाने की तारीख से 15 दिन की अवधि के भीतर ऐसे केबल प्रचालक को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की प्रति सौंपे और इस संबंध में एक पावती प्राप्त करे।"

6. प्रधान विनियमों के विनियम 13.2क में,—

(क) विनियम 13.2क.1 के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"13.2क.1 प्रत्येक प्रसारक जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा ऐसे प्रारंभ के पश्चात ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर उस तारीख को विद्यमान तथा तीस दिन की उक्त अवधि के भीतर अस्तित्व में आने वाले सभी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों को अपना संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव सूचित करेगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, डायरेक्ट-टु-होम प्लेटफार्म हेतु अंतरसंयोजन के लिए तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन एवं शर्तों को विनिर्दिष्ट किया गया होगा, जिनमें इन विनियमों की अनुसूची III में सूचीबद्ध निबंधन और शर्तें भी शामिल होंगी।

परंतु यह कि कोई भी प्रसारक, प्रत्यक्षतः और अप्रत्यक्षतः, सब्सक्राइबर्स के किसी भी वर्ग को, जिनमें वाणिज्यिक सब्सक्राइबर भी शामिल हैं, इसकी डायरेक्ट-टु-होम सेवा उपलब्ध न कराने के लिए किसी डायरेक्ट-टु-होम प्रचालक को बाध्य नहीं करेगा।

परंतु यह और कि कोई प्रसारक डायरेक्ट-टु-होम प्रचालकों द्वारा सिगनलों की आपूर्ति के लिए विभिन्न संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव रख सकेगा।

(क) वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए, अर्थात् :-

- (i) तीन सितारा और उससे अधिक की रेटिंग वाले होटल;
- (ii) हेरिटेज होटल (जैसाकि पर्यटन विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के लिए दिशा-निर्देशों में वर्णित हैं);
- (iii) कोई अन्य होटल, मोटल, इन अथवा ऐसी ही अन्य वाणिज्यिक स्थापना जो आवास एवं भोजन उपलब्ध करा रही है तथा जिसमें पचास अथवा अधिक कमरे हैं; और

(ख) किसी विशेष आयोजन के अवसर पर मनोरंजन कर विधि के तहत पंजीकृत किसी ऐसे स्थान पर, जिसके लिए भुगतान के आधार पर न्यूनतम पचास व्यक्तियों के लिए एक्सेस की अनुमति दी गई है, आम अवलोकन के लिए ऐसे प्रसारक के कार्यक्रमों के संबंध में।

स्पष्टीकरण :

शंकाओं के समाधान के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि साधारण सब्सक्राइबर्स को सिगनलों के प्रावधान के लिए किसी प्रसारक द्वारा प्रकाशित संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव, जिनमें वाणिज्यिक निबंधनों सहित विभिन्न निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट हैं, ऐसे वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स को सिगनलों के प्रावधान के लिए भी लागू होंगे, जो द्वितीय परंतुक में निर्दिष्ट नहीं हैं।

(ख) विनियम 13.2क.2 के परंतुक में, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ग) विनियम 13.2क.3 में,—

(i) "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी; और

(ii) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(घ) विनियम 13.2क.4 में,—

(i) "नब्बे दिन" शब्दों के स्थान पर, "तीस दिन" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; और

(ii) "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(ङ.) विनियम 13.2क.6 में,—

(i) उप-विनियम (1) के द्वितीय परंतुक में, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी; और

(ii) उप-विनियम (2) और उप-विनियम (3) में, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (चौथा संशोधन) विनियम, 2007 (2007 का 9)" शब्दों और संख्याओं के स्थान पर, "दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4)" शब्द और संख्याएं प्रतिस्थापित की जाएंगी;

(च) विनियम 13.2क.11 के परंतुक में, "समस्त बुके" शब्दों के स्थान पर, "कोई चैनल अथवा चैनल अथवा बुके" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

7. प्रधान विनियमों में, विनियम 13.2क.13 के पश्चात्, निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"13.2ख. डायरेक्ट-टु-होम के अलावा एड्रसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव.

13.2ख.1 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व प्रसारण सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा ऐसे प्रारंभ के पश्चात् ऐसी सेवाएं प्रदान करना जारी रखता है, ऐसे प्रारंभ की तारीख से तीस दिन के भीतर अपना संदर्भ अंतरसंयोजन प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें अन्य बातों

के साथ-साथ, निम्न को छोड़कर एड्रसेबल प्रणालियों के साथ अंतरसंयोजन के लिए अनुसूची III में सूचीबद्ध निबंधन और शर्तें भी शामिल होंगी—

(क) केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में केबल सेवा;

(ख) डायरेक्ट-टु-होम सेवा।

13.2ख.2 प्रत्येक प्रसारक, जो दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 (2009 का 4) के प्रारंभ होने की तारीख के पश्चात प्रसारण सेवाएं शुरू करता है, ऐसे प्रारंभ से तीस दिन के भीतर अथवा ऐसी सेवाएं प्रदान करने से पूर्व, जो भी बाद में हो, प्राधिकरण को, अपना संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जिसमें उप-विनियम 13.2ख.1 में निर्दिष्ट तकनीकी और वाणिज्यिक निबंधन और शर्तें निर्दिष्ट की गई होंगी तथा इसे ऐसी सूचना से पूर्व तथा उसके साथ-साथ अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

13.2ख.3 डायरेक्ट-टु-होम सेवा के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव से संबंधित विनियम 13.2क.1, 13.2क.2, 13.2क.4, 13.2क.5, 13.2क.6, 13.2क.7, 13.2क.8, 13.2क.9, 13.2क.10, 13.2क.11, 13.2क.12 और 13.2क.13 के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों सहित, केबल टेलीविजन (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 4क की उप-धारा (1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित केबल सेवाओं तथा डायरेक्ट-टु-होम सेवा को छोड़कर, एड्रसेबल प्रणालियों के साथ अंतरसंयोजन के लिए ऐसे किसी संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव पर लागू होंगे।

परंतु यह कि कोई प्रसारक विभिन्न प्रकार की एड्रसेबल प्रणालियों के लिए विभिन्न संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव रख सकेगा।

13.2ख.4 टीवी चैनलों का कोई वितरक जो टीवी चैनलों के वितरण के लिए एक एड्रसेबल प्रणाली का प्रयोग कर रहा है तथा, यथास्थिति, विनियम 13.2ख.1 और विनियम 13.2ख.2 में निर्दिष्ट संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव के निबंधनों के अनुसार किसी प्रसारक से अंतरसंयोजन प्राप्त कर रहा है, यह सुनिश्चित करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग की जा रही एड्रसेबल प्रणाली, एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों की पूर्ति करती है, जैसाकि इन विनियमों की अनुसूची IV में निर्दिष्ट है।

परंतु यह कि ऐसे मामलों में, जहां प्रसारक की यह राय है कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग में लाई जा रही एड्रसेबल प्रणाली इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों की पूर्ति नहीं करती है, तो प्रसारक द्वारा ऐसी राय से सूचित किए जाने पर, टीवी चैनलों का वितरक एड्रसेबल प्रणाली की लेखापरीक्षा मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि0 अथवा ऐसी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाअधिसूचित किसी अन्य एजेंसी से कराएगा तथा इस आशय का एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग में लाई जा रही एड्रसेबल प्रणाली इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों की पूर्ति करती है।

परंतु यह भी कि टीवी चैनलों के वितरण के लिए प्रयोग में लाई जा रही एड्रसेबल प्रणाली के बारे में, प्रथम परंतुक में यथानिर्दिष्ट ऐसी लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विनियमों की अनुसूची IV में यथाविनिर्दिष्ट एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों से संतुष्ट होने अथवा संतुष्ट न होने के बारे में, यथास्थिति, मैसर्स ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लि० अथवा इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी के निष्कर्ष अंतिम होंगे।”।

8. प्रधान विनियमों में, अनुसूची II के पश्चात्, निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“अनुसूची III

निबंधन और शर्तें जो डायरेक्ट-टु-होम प्लेटफार्म के लिए तथा अन्य एड्रसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव का अनिवार्यतः भाग होनी चाहिए

लाइसेंस शुल्क	<p>करार की अवधि के दौरान प्रत्येक माह के लिए अथवा उसके भाग के लिए डीटीएच प्रचालक(प्रसारक का नाम) को मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा जो वह दर होगी जिसे मासिक औसत सब्सक्राइबर स्तर से गुणा किया जाएगा।</p> <p>प्रति सब्सक्राइबर अलाकार्ट और बुके “दर” का आकलन इस आरआईओ के अनुबंध में किया गया है। इस आरआईओ के अनुबंध में उल्लिखित दरों में, जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, सभी कर और उद्ग्रहण शामिल नहीं हैं।</p> <p>“मासिक औसत सब्सक्राइबर स्तर” संदर्भाधीन माह के पहले और अंतिम दिन को सब्सक्राइबरों की संख्या के योग, जिसे 2 से विभाजित किया गया है, के समान है।</p> <p>.....(प्रसारक का नाम) को संदेय मासिक लाइसेंस शुल्क के आकलन के प्रयोजनार्थ “सब्सक्राइबर” का आशय है, किसी कैलेंडर माह के लिए, प्रत्येक सेट टॉप बॉक्स, जोकि कि डीटीएच प्रचालक के माध्यम से(प्रसारक का नाम) के चैनल(लों) को प्राप्त कर रहा है।</p> <p>लाइसेंस शुल्क का आकलन :</p> <p>1. यदि कोई डीटीएच प्रचालक.....(प्रसारक का नाम) के एक अथवा अधिक बुके लेता है :</p> <p>(क) यदि डीटीएच प्रचालक अपने डीटीएच सब्सक्राइबरों को समग्र रूप से बुके प्रदान कर रहा है, तो ऐसे बुके के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क अनुबंध में यथाआकलित बुके दर के समान होगा जिसे बुके प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबरों की संख्या की मासिक औसत संख्या से गुणा किया जाएगा।</p>
---------------	---

(ख) यदि डीटीएच प्रचालक अपने डायरेक्ट-टु-होम सब्सक्राइबर्स को ऐसे विकल्पित बुके समग्र रूप से प्रदान नहीं कर रहा है बल्कि ऐसे बुके में शामिल केवल कुछ चैनल प्रदान कर रहा है अथवा ऐसे विकल्पित बुके में शामिल चैनलों को इस प्रकार पैकेज कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे विकल्पित बुके में शामिल विभिन्न चैनलों के लिए विभिन्न सब्सक्राइबर आधार बन रहा हो, तो डीटीएच प्रचालक द्वारा ऐसे समस्त विकल्पित बुके के लिए (प्रसारक का नाम) को भुगतान का आकलन उस चैनल के लिए सब्सक्राइबर बेस के आधार पर किया जाएगा जिसका बुके में शामिल चैनल के बीच सर्वोच्च सब्सक्राइबर आधार है।

II. यदि डीटीएच प्रचालक कला-कार्टे आधार पर (प्रसारक का नाम) का एक अथवा अधिक सभी चैनल लेता है :

(क) यदि डीटीएच प्रचालक अपने-अपने डीटीएच सब्सक्राइबर्स को चैनल अला-कार्टे आधार पर प्रदान कर रहा है, तो ऐसे अला-कार्टे चैनलों के लिए मासिक लाइसेंस शुल्क अनुबंध में यथाआकलित अला-कार्टे दर के समान होगा जिसे अला-कार्टे बेस पर पर चैनल प्राप्त कर रहे सब्सक्राइबर्स की औसत संख्या से गुणा किया जाएगा।

(ख) यदि डीटीएच प्रचालक अपने डायरेक्ट-टु-होम सब्सक्राइबर को कला-कार्टे के रूप में ऐसे विकल्पित अला-कार्टे चैनल प्रदान नहीं करता है, परंतु पैकेजों में अला-कार्टे प्रदान करता है, तो प्रत्येक अला-कार्टे चैनल के लिए (प्रसारक का नाम) को भुगतान का आकलन उस पैकेज में सब्सक्राइबर बेस के आधार पर किया जाएगा, जिसमें ऐसा विकल्पित अला-कार्टे चैनल रखा गया है।

III. यदि कोई डीटीएच प्रचालक अला-कार्टे दर के आधार पर एक अथवा अधिक चैनल प्राप्त करता है और ऐसे विभिन्न बुके भी चुनता है जिसमें (प्रसारक का नाम) के अला-कार्टे आधार पर विकल्पित चैनल शामिल नहीं है :

(क) बुके के लिए, मासिक लाइसेंस शुल्क का आकलन उपर्युक्त उप-खंड I के आधार पर किया जाएगा।

(ख) अला-कार्टे चैनलों के लिए, मासिक लाइसेंस शुल्क का आकलन उपर्युक्त उप-खंड II के आधार पर किया जाएगा।

लाइसेंस शुल्क का भुगतान समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुरूप किसी विधारित कर/टीडीएस की कटौती के अधधीन होगा।

भुगतान के निबंधन मासिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान (प्रसारक का नाम) द्वारा बिना किसी कटौती के डीटीएच प्रचालक की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत किए गए बीजक की प्राप्ति के पन्द्रह (15) दिन के भीतर मासिक आधार पर बकाये में बिना किसी कटौती के किया जाएगा सिवाए विधारित कर/टीडीएस की कटौती को छोड़कर, जैसाकि इस आरआईओ में उपबंधित है।

	<p>प्रत्येक माह की समाप्ति के सात दिन के भीतर, डीटीएच प्रचालक उस माह के लिए सब्सक्राइबर्स की ओपनिंग, क्लोजिंग और औसत संख्या उपलब्ध करेगा, जिसके आधार पर(प्रसारक का नाम) डीटीएच प्रचालक को बीजक प्रस्तुत करेगा। यदि डीटीएच प्रचालक सात दिन की उक्त अवधि के भीतर रिपोर्ट भेजने में असफल रहता है, तो(प्रसारक का नाम) को अधिकार होगा वह एक अनंतिम बीजक प्रस्तुत करे तथा डीटीएच प्रचालक इस रण्ड के निबंधनों के अनुरूप ऐसे अनंतिम बीजक के आधार पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए बाध्य होगा। तथापि, अनंतिम बीजक उस राशि के लिए होना चाहिए जो डीटीएच प्रचालक द्वारा तत्काल पूर्व माह के लिए अदा किए जाने वाले मासिक लाइसेंस शुल्क की राशि से अनधिक हो। डीटीएच प्रचालक से रिपोर्ट की प्राप्ति पर, पक्ष(प्रसारक का नाम) द्वारा प्रस्तुत किए गए अनंतिम बीजक तथा डीटीएच प्रचालक द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के बीच आपसी सहमति के लिए कार्रवाई करेंगे।</p> <p>डीटीएच प्रचालक के लिए निर्दिष्ट निबंधनों के अनुरूप देय तिथि तक भुगतान करना अपेक्षित होगा तथा डीटीएच प्रचालक की ओर से ऐसे करने में किसी भी असफलता का अर्थ इसके तहत वास्तविक उल्लंघन कारित करेगा। विलंब से किए गए भुगतानों के लिए ब्याज वसूला जाएगा जिसका आकलन उस तारीख से, जिसको भुगतान देय था, लेकर उस तारीख तक प्रतिशत की यथानुपात मासिक दर से किया जाएगा, जिसको कि पूरा भुगतान किया गया। विलंब से किए गए भुगतानों पर ब्याज का अधिरोपण तथा संग्रहण देय तारीख तक लाइसेंस शुल्क अदा करने के डीटीएच प्रचालक के दायित्वों को समाप्त नहीं करेगा तथा(प्रसारक का नाम) करार के अंतर्गत अपने अन्य सभी अधिकारों तथा उपचारों को बनाए रखेगा।</p> <p>इसके अंतर्गत लाइसेंस शुल्क के समस्त भुगतानों में समस्त लागू अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं हैं, जिनमें सभी और कोई सेवा कर, वैट, कार्य संविदा कर, सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, मनोरंजन कर तथा ऐसे कर शामिल हैं। सभी ऐसे कर डीटीएच प्रचालक की लागत पर होंगे तथा डीटीएच प्रचालक से(प्रसारक का नाम) द्वारा विद्यमान दरों पर प्रभारित किए जाएंगे।</p> <p>यदि लाइसेंस शुल्क का भुगतान यथासंशोधित भारतीय आयकर अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुरूप विर्सि विधारित कर/डीटीएस की कटौती के अध्वधीन है, तो डीटीएच प्रचालक ऐसे अवधि के भीतर जैसीकि आयकर अधिनियम/उसके अंतर्गत जारी नियम/अधिसूचनाओं/परिपत्रों में निर्दिष्ट की गई है,(प्रसारक का नाम) को कर विधारित प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराएगा।</p>
वितरण और सुरक्षा	<p>सभी(प्रसारक का नाम) चैनल डीटीएच प्रचालक द्वारा सब्सक्राइबर को सुरक्षित एंक्रिप्टेड तरीके और बिना किसी परिवर्तन के वितरित किए जाने चाहिए।</p> <p>डीटीएच प्रचालक द्वारा अपने सब्सक्राइबर्स को(प्रसारक का नाम) चैनलों के प्रसारण सिगनल के संबंध में डीटीएच प्रचालक द्वारा आवंटित अपलिंक विनिर्देशनों, उपग्रह क्षमता तथा अवसरचना उसके डीटीएच प्लेटफार्म में समान विषय-वस्तु की भीतर किसी अन्य चैनल के प्रसारण सिगनल से खराब नहीं होगी।</p>

एंटी पायरेसी किसी चैनल, पूर्णतया अथवा उसके किसी भाग की, चोरी, पायरेसी, अनधिकृत री-ट्रांसमिशन, पुनर्वितरण, अथवा प्रदर्शन, नकल अथवा प्रतिकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक तौर पर "पायरेसी" कहा गया है) को रोकने के उद्देश्य से डीटीएच प्रचालक करार की अवधि के प्रारंभ से पूर्व तथा अवधि के दौरान सभी अवसरों पर,(प्रसारक का नाम) द्वारा समय-समय पर, गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से, लिखित में, यथानिर्दिष्ट (सुरक्षा विनिर्देशनों), पूर्णतया प्रभावी सशर्त उपागम वितरण और कंटेंट संरक्षण तथा सुरक्षा प्रणालियाँ और संबद्ध भौतिक सुरक्षा तथा प्रचालनात्मक पद्धतियाँ (जिसे इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से "सुरक्षा प्रणालियाँ" कहा गया है) तैनात, अनुरक्षित और प्रवर्तित करेगा।

करार में निर्दिष्ट सुरक्षा अपेक्षाओं के संबंध में डीटीएच प्रचालक के अनवरत अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु(प्रसारक का नाम) के लिए तकनीकी लेखापरीक्षाओं ("तकनीकी लेखापरीक्षा") की आवश्यकता होगी, जिन्हें(प्रसारक का नाम) की लागत और व्यय पर, अवधि के दौरान प्रतिवर्ष दो वर्ष से अधिक बार के लिए(प्रसारक का नाम) द्वारा लिखित में अनुमोदित एक स्वतंत्र प्रतिभूति प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षक ("तकनीकी लेखापरीक्षक") द्वारा संचालित किया जाएगा। यदि किसी तकनीकी लेखापरीक्षक के परिणामों को डीटीएच प्रचालक अथवा(प्रसारक का नाम) द्वारा संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो(प्रसारक का नाम) डीटीएच प्रचालक को अधिसूचित करेगा तथा(प्रसारक का नाम) आगामी चौदह (14) कार्य दिवसों में इस मुद्दे के निपटान के लिए डीटीएच प्रचालक के साथ कार्रवाई करेगा। यदि तब भी कोई समाधान नहीं निकलता है, तथा(प्रसारक का नाम) अपने स्वयं के विवेक पर, चैनलों के वितरण करने के डीटीएच प्रचालक के अधिकार तब तक निलंबित कर सकेगा अथवा करार के अंतर्गत यथाउपबंधित कोई, अन्य कार्रवाई कर सकेगा, जब तक कि ऐसी प्रणालियों, पद्धतियों तथा सुरक्षा उपायों को(प्रसारक का नाम) की संतुष्टि के अनुरूप सही न कर दिया गया हो। डीटीएच प्रचालक यह सत्यापित करने के लिए कि प्रणालियों, पद्धतियों और सुरक्षा उपायों को डीटीएच प्रचालक द्वारा(प्रसारक का नाम) की संतुष्टि के अनुसार सही कर दिया गया है, किसी पश्चातवर्ती तकनीकी लेखापरीक्षा की लागत और व्यय का वहन करेगा।

डीटीएच प्रचालक इसके प्लेटफार्म के माध्यम से वितरित/प्रसारित किए गए चैनलों की किसी चोरी, कॉपी राइट के उल्लंघन तथा उनके अनधिकृत अवलोकन का पता लगाने के लिए कम-से-कम प्रत्येक 10 मिनट पर 24X7X365(6) आधार पर फिंगर प्रिंटिंग तंत्र स्थापित करेगा।

डीटीएच प्रचालक ऐसे समय पर जब चैनल उपलब्ध कराए गए हों, किसी चैनल के किसी भाग को डीटीएच प्रचालक द्वारा वितरण के अलावा उसे रिकॉर्ड करने, प्रतिकृति तैयार करने, केबलकास्ट करने, प्रदर्शित करने अथवा डीटीएच प्रचालक द्वारा वितरण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राधिकृत, कारित अथवा आक्रांत नहीं करेगा। यदि डीटीएच प्रचालक को यह ज्ञात होता है कि कोई अनधिकृत तीसरा पक्ष किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी चैनल अथवा सभी चैनलों को रिकॉर्ड कर रहा है, प्रतिकृति तैयार

	<p>कर रहा है, केबल कास्टिंग कर रहा है अथवा अन्यथा उपयोग कर रहा है, तो डीटीएच प्रचालक ऐसी रिकार्डिंग, डुप्लीकेटिंग, केबलकास्टिंग, प्रदर्शन अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए किसी अथवा सभी चैनलों के अन्यथा प्रयोग के बारे में ऐसे अवगत होने से दस मिनट के भीतर (प्रसारक का नाम) को अधिसूचित करेगा और डीटीएच प्रचालक भी ऐसे अनधिकृत प्रयोग को रोकने के लिए संबंधित सेट टॉप बॉक्स को बंद कर देगा। तथापि, पर्सनल वीडियो रिकार्डर/डिजिटल वीडियो रिकार्डर सुविधा, जोकि डीटीएच प्रचालक द्वारा उपलब्ध कराई गई है, के साथ सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग उस समय तक अनधिकृत प्रयोग नहीं माना जाएगा, जब तक कि ऐसे सेट टॉप बॉक्स का प्रयोग प्रत्येक डीटीएच प्रचालक तथा सब्सक्राइबर के बीच सब्सक्रिप्शन करार के निबंधनों और शर्तों के अनुरूप किया जा रहा है।</p> <p>यदि (प्रसारक का नाम) द्वारा सूचना (जैसाकि नीचे परिभाषित किया गया है) के माध्यम से ऐसे निदेशित किया गया हो, तो डीटीएच प्रचालक (प्रसारक का नाम) से ऐसा आदेश प्राप्त होने के समय से दस मिनट के भीतर किसी अनधिकृत सब्सक्राइबर/पाइरेसी में सलिप्त सब्सक्राइबर को प्रसारण बंद कर देगा अथवा गैर-प्राधिकृत कर देगा। इस खंड के अंतर्गत किसी सूचना को केवल तभी वैध सूचना के रूप समझा जाएगा यदि (i) सूचना पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत प्रपत्र में ई-मेल के माध्यम से भेजी गई है तथा (ii) सूचना ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा भेजी गई है जो ऐसी सूचना को भेजने के लिए नामनिर्दिष्ट है। तथापि, "सूचना" (प्रसारक का नाम) के प्रतिनिधियों द्वारा संप्रेषण के अन्य साधनों जैसे टेलीफोन संदेश, फैक्स आदि के माध्यम से भी उपलब्ध कराई जा सकती है तथा उक्त "सूचना" की पुष्टि बाद में (प्रसारक का नाम) द्वारा ई-मेल के माध्यम से की जाएगी तथा डीटीएच प्रचालक ऐसी सूचना पर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होगा।</p>
रिपोर्ट	<p>डीटीएच प्रचालक अपने स्वयं के व्यय पर सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली ("एसएमएस") का अनुरक्षण करेगा जोकि कैस (सर्शत उपागम प्रणाली) के साथ पूरी तरह से एकीकृत होनी चाहिए।</p> <p>डीटीएच प्रचालक (प्रसारक का नाम) को (प्रसारक का नाम) द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रपत्र में प्रत्येक माह की समाप्ति से सात (7) दिन के भीतर (प्रसारक का नाम) चैनलों को अंतर्विष्ट करने वाले टियर और/अथवा पैकेज तथा (प्रसारक का नाम) चैनलों के लिए पूर्ण एवं सही ओपनिंग एवं क्लोजिंग मासिक रिपोर्टें उपलब्ध कराएगा।</p> <p>ऐसी रिपोर्टों में मासिक औसत सब्सक्राइबर स्तर (जिसमें शामिल हैं, परंतु जो प्रत्येक (प्रसारक का नाम) चैनल तथा प्रत्येक पैकेज जिसमें (प्रसारक का नाम) चैनल शामिल है, के लिए सब्सक्राइबरों की संख्या तक सीमित नहीं है) के आकलन के लिए अपेक्षित समस्त जानकारी तथा (प्रसारक का नाम) को देय लाइसेंस शुल्क, निर्दिष्ट होगा तथा इसे ऐसे अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एवं प्रमाणित किया जाएगा जो विभागाध्यक्ष/मुख्य वित्तीय अधिकारी से नीचे की पंक्ति का न हो जो यह प्रमाणित करेगा कि रिपोर्ट में समस्त जानकारी सत्य और सही है।</p>

लेखापरीक्षा

.....(प्रसारक का नाम) के प्रतिनिधियों के पास, एक कैलेण्डर वर्ष में दो से अनधिक बार, करार के अंतर्गत(प्रसारक का नाम) को समुचित रूप से भुगतानयोग्य राशियों, सब्सक्राइबर रिपोर्टों में अंतर्विष्ट जानकारी तथा करार के निबंधनों और शर्तों के पूर्ण अनुपालन के सत्यापन के प्रयोजनार्थ सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली, सर्जित उपागम प्रणाली, अन्य संबद्ध प्रणालियों, प्रसारक द्वारा उपलब्ध कराए गए चैनलों से संबंधित सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली के अभिलेखों की पुनरीक्षा करने और/अथवा लेखापरीक्षा कराने का अधिकार होगा। यदि ऐसी पुनरीक्षा और/अथवा लेखापरीक्षा से पता चलता है कि(प्रसारक का नाम) को अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किया जाना है, तो डीटीएच प्रचालक तत्काल ऐसे शुल्क का भुगतान विलांबित भुगतान ब्याज दर की बढी हुई राशि के अनुसार कर देगा। यदि किसी अवधि के लिए देय कोई शुल्क डीटीएच प्रचालक द्वारा प्रतिवेदित ऐसी किसी अवधि के लिए देय बनने वाले शुल्क से दो (2) प्रतिशत अथवा उससे ज्यादा हो जाता है, तो डीटीएच प्रचालक ऐसी पुनरीक्षा और/अथवा लेखापरीक्षा के संबंध में उपगत(प्रसारक का नाम) की समस्त लागत का भुगतान कर देगा तथा भविष्य में ऐसी त्रुटियों से बचने के लिए आवश्यक कार्रवाई करेगा।

डीटीएच प्रचालक करार के अंतर्गत डीटीएच प्रचालक द्वारा संकलित किए गए समस्त ग्राहक डाटाबेस का एकमात्र स्वामी और धारक होगा।

डीटीएच प्रचालक अपने स्वयं के व्यय पर एक सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली ("एसएमएस") का अनुरक्षण करेगा, जो कम-से-कम, निम्नलिखित के लिए सक्षम होगी:-

(i) एक कम्प्यूटरीकृत ग्राहक डाटाबेस का अनुरक्षण करने के लिए जो नाम, पते, भुगतान एवं बिलिंग की घुनी गई पद्धति सहित प्रत्येक सब्सक्राइबर के पर्याप्त विवरणों की रिकॉर्डिंग में सक्षम होगी;

(ii) नए सब्सक्राइबरों के लिए अनुबंधों को तैयार करने और वितरित करने के द्वारा सब्सक्राइबरों के सब्सक्रिप्शनों को प्रशासित करने तथा ऐसी अवसंरचना की स्थापना और अनुरक्षण करने में, जिसके द्वारा अनवरत प्रशासन के लिए एसएमएस डाटाबेस में सब्सक्राइबरों के अनुबंध संग्रहित और रिकार्ड किए जाते हैं;

(iii) सब्सक्राइबरों के संबंध में, समस्त अनवरत प्रशासनिक कृत्यों के निपटान में जिसमें, बिना सीमा के, सब्सक्रिप्शन भुगतानों की बिलिंग और संग्रहण, ऋण नियंत्रण, विक्रय पूछताछ तथा शिकायतों का निपटान शामिल है;

(iv) प्रोग्रामिंग पैकेजों के सब्सक्राइबरों को बिक्री के लिए डीटीएच प्रचालक के प्राधिकृत एजेंटों को समय-समय पर देय किसी कमीशन फीस के भुगतानों को प्रशासित करना;

(v) रिसीवरों तथा स्मार्टकार्डों, यदि लागू हैं, को प्राप्त करना व सब्सक्राइबरों को उनका वितरण करना, तथा अपने विवेक के अनुसार समय-समय पर रिप्लेसमेंट स्मार्टकार्ड जारी करना और

(vi) एमएसएम ओवर-द-एयर एड्रेसिंग प्रणाली के माध्यम से नए सब्सक्राइबरों को समर्थ बनाना तथा दोषपूर्ण सब्सक्राइबरों को अपने विवेक के अनुसार, समय-समय, पर अशक्त करना।

अवधि	<p>जैसीकि(प्रसारक का नाम) तथा डीटीएच प्रचालक के बीच पारस्परिक सहमति से तय की जाए, जोकि करार को हस्ताक्षर करने की तारीख से न्यूनतम एक (1) वर्ष के अध्यक्षीन होगी, जब तक कि यह करार के अनुरूप पहले समाप्त न हो जाए।</p> <p>करार के अवधि को पक्षों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत निबंधनों और शर्तों पर बढ़ाया जा सकेगा तथा जिसे लिखित में दर्ज किया जाएगा।</p>
समाप्ति	<p>किसी भी पक्ष को निम्नलिखित के होने पर, लागू विधि के अध्यक्षीन, दूसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस द्वारा इस करार को समाप्त करने का अधिकार है:—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. दूसरे पक्ष द्वारा इस करार के वास्तविक उल्लंघन पर जिसे तीस (30) दिन के भीतर, ठीक न किया गया हो, जोकि लिखित में ऐसा करने के लिए अपेक्षित अवधि है; 2. दीवालिएपन, परिक्षीणता तथा अन्य पक्ष की परिसंपत्तियों पर प्राप्तकर्ता की नियुक्ति पर; 3. डीटीएच प्रचालकों अथवा इसकी डीटीएच सेवा को प्रचालित करने के लिए आवश्यक किसी अन्य वास्तविक लाइसेंस के उस समय रद्द होने पर, जोकि डीटीएच प्रचालक के दोष के कारण के अलावा हुआ हो। <p>.....(प्रसारक का नाम) के पास डीटीएच प्रचालक को लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त करने का अधिकार होगा यदि (i) डीटीएच प्रचालक चोरी-प्रतिरोधी अपेक्षाओं में से किसी का उल्लंघन करता है तथा दस (10) दिन के भीतर ऐसे उल्लंघन का उपचार करने में असफल रहता है, जोकि ऐसा करने के लिए लिखित में दी गई अवधि है, अथवा</p> <p>(ii)(प्रसारक का नाम) क्षेत्र में सभी वितरकों के संबंध में(प्रसारक का नाम) चैनल को बंद कर देता है तथा डीटीएच प्रचालक को न्यूनतम नब्बे (90) दिन का पूर्व-लिखित नोटिस प्रदान करता है।</p> <p>डीटीएच प्रचालक (प्रसारक का नाम) को लिखित नोटिस देकर इस करार को समाप्त करने का अधिकार रखता है, यदि डीटीएच प्रचालक अपने डीटीएच व्यवसाय को बंद कर देता है और न्यूनतम नब्बे (90) दिन का पूर्व-लिखित नोटिस प्रदान करता है।</p>
अधिकार क्षेत्र	<p>विनियंत्रण विधि भारतीय विधि होगी तथा टीडीसैट के पास करार के कारण/के संबंध में अथवा इसके परिणामस्वरूप पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के संबंध में अनन्य अधिकार क्षेत्र होगा।</p>

टिप्पणी:— उपर्युक्त अनुसूची में आने वाले "डीटीएच प्रचालक" पदबंध को एड्रेसेबल प्लेटफार्म के प्रतीतात्मक उपयुक्त पदनाम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा जिसके लिए प्रसारक द्वारा संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव जारी किया जाना है।

(ख) बुके की दरें

बुके-1

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु०)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

बुके-2

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु०)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

बुके-3

चैनल	डीटीएच प्रचालक को दर (रु०)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

अनुसूची IV

डिजिटल एड्रेसेबल प्रणालियों के क्रियान्वयन के लिए सेट टॉप बॉक्स (एसटीबी), सशर्त उपागम प्रणाली (कैस) और सब्सक्राइबर प्रबंधन प्रणाली (एसएमएस) के लिए विनिर्देशन

(क) एसटीबी अपेक्षाएं:

1. सभी एसटीबी में एम्बेडेड उपागम एक्सेस होनी चाहिए।
2. एसटीबी को हैडएंड द्वारा इंसर्ट किए गए सशर्त उपागम की डीक्रिप्टिंग करने में समर्थ होना चाहिए।
3. एसटीबी को प्रत्यक्ष फिंगर प्रिंटिंग करने में समर्थ होना चाहिए। एसटीबी एंटाइटलमेंट कंट्रोल मैसेज (ईसीएम) एवं एंटाइटलमेंट मैनेजमेंट मैसेज (ईएमएम), दोनों पर आधारित फिंगर प्रिंटिंग को समर्थित करना चाहिए।
4. एसटीबी हैडएंड से वैयक्तिक रूप से एड्रेसेबल होना चाहिए।
5. एसटीबी हैडएंड से मैसेजिंग लेने में समर्थ होना चाहिए।
6. मैसेजिंग कैरेक्टर क्षमता न्यूनतम 120 कैरेक्टर होनी चाहिए।
7. इसमें वैश्विक मैसेजिंग, ग्रुप मैसेजिंग तथा वैयक्तिक एसटीबी मैसेजिंग के लिए प्रावधान होना चाहिए।
8. एसटीबी में फ़ोरवर्ड मैसेजिंग क्षमता होनी चाहिए।
9. एसटीबी बीआईएस के अनुरूप होना चाहिए।
10. डिक्रिप्शन तथा डिक्म्प्रेसन के बीच कंटेंट प्राप्त करने के लिए एसटीबी के भीतर एक प्रणाली होनी चाहिए।
11. ओवर-द-एयर (ओटीए) सॉफ्टवेयर अपग्रेड को सुकर बनाने के लिए एसटीबी ओवर-द-एयर एड्रेसेबल होना चाहिए।

(ख) फिंगरप्रिंटिंग आवश्यकताएं:

1. फिंगर प्रिंटिंग रिमोट पर कोई कुंजी दबाने के द्वारा रिमूवेबल नहीं होनी चाहिए।
2. फिंगर प्रिंटिंग वीडियो की सबसे ऊपरी लेयर पर होनी चाहिए।
3. फिंगर प्रिंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि यह विशेष एसटीबी संख्या अथवा विशेष व्यूविंग कार्ड (वीसी) संख्या को पहचान सके।
4. फिंगर प्रिंटिंग एसटीबी की सभी स्क्रीनों पर प्रदर्शित होनी चाहिए जैसे मीनू, ईपीजी आदि।
5. फिंगर प्रिंटिंग की लोकेशन हैडएंड से परिवर्तनीय होनी चाहिए तथा व्यूविंग उपस्कर पर यादृच्छिक होनी चाहिए।
6. फिंगर प्रिंटिंग कैरेक्टरों की संख्या को देने में सक्षम होनी चाहिए ताकि यूनीक एसटीबी और/अथवा वीसी की पहचान की जा सके।
7. फिंगर प्रिंटिंग ग्लोबल तथा साथ ही वैयक्तिक एसटीबी आधार पर संभव होनी चाहिए।
8. प्रत्यक्ष फिंगर प्रिंटिंग तथा संबंधित प्रसारकों के ऑन-स्क्रीन डिस्प्ले (ओएसडी) संदेश समय, स्थान, अवधि तथा फ्रीक्वेंसी के संबंध में बिना किसी परिवर्तन के प्रदर्शित होने चाहिए।
9. किसी सामान्य इंटरफेस ग्राहक परिसर उपस्कर (सीपीई) का प्रयोग न किया जाए।
10. एसटीबी के पास प्रावधान होना चाहिए कि ओएसडी कभी भी अशक्त न हो।

(ग) कैस तथा एसएमएस आवश्यकताएं:

1. सर्शत उपागम प्रणाली के चालू संस्करण का हैकिंग का कोई इतिहास नहीं होना चाहिए।
2. फिंगर प्रिंटिंग किसी अन्य उपस्कर अथवा सॉफ्टवेयर के प्रयोग द्वारा अवैध नहीं हो जानी चाहिए।
3. एसटीबी तथा वीसी को सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हैडएंड से पियर करना चाहिए।
4. एक्टिवेशन तथा डीएक्टिवेशन प्रक्रिया के लिए एसएमएस तथा सीए को एसएमएस से एकीकृत करना चाहिए तथा ऐसा दोनों प्रणालियों के माध्यम से एक-साथ किया जाना चाहिए। इसके अलावा, सीए प्रणाली सभी एक्टिवेशनों और डीएक्टिवेशनों के लॉग सृजित करने में स्वतंत्र रूप से समर्थ होनी चाहिए।
5. हैकिंग के ज्ञात मामले में, सीए कंपनी सीए के उन्नयन में क्षमता रखने वाली होनी चाहिए।
6. एसएमएस तथा कैस, चैनल द्वारा चैनल पर तथा एसटीबी द्वारा एसटीबी आधार पर सब्सक्राइबर्स को वैयक्तिक रूप से एड्रेस करने में सक्षम होने चाहिए।
7. एसएमएस कम्प्यूटरीकृत होना चाहिए तथा सब्सक्राइबर्स से सरोकार रखने वाली महत्वपूर्ण जानकारी और आंकड़ों को रिकार्ड करने में समर्थ होना चाहिए, जैसे:

- क) विशेष ग्राहक आईडी
- ख) सब्सक्रिप्शन अनुबंध संख्या
- ग) सब्सक्राइबर का नाम
- घ) बिलिंग पता
- ड) स्थापना पता
- च) लैंडलाइन नम्बर
- छ) मोबाइल नम्बर
- ज) ई-मेल आईडी
- झ) को सब्सक्राइबर की गई सेवा/पैकेज
- ञ) विशेष एसटीबी संख्या
- ट) विशेष वीसी संख्या

8 एसएमएस निम्नलिखित करने के लिए सक्षम होना चाहिए:

- क) एक्टिवेशन, डीएक्टिवेशन आदि के संदर्भ में ऐतिहासिक आंकड़ों का अवलोकन तथा मुद्रण।
- ख) प्रत्येक तथा हर सेट टॉप बॉक्स, वीसी यूनिट का पता लगाने में।
- ग) एसएमएस किसी अपेक्षित समय पर निम्नलिखित की रिपोर्टिंग करने में सक्षम होना चाहिए।

- i) प्राधिकृत किए गए सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या
- ii) नएवर्क में सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या
- iii) किसी विशेष तरीके का कोई विशेष सेवा सब्सक्राइबर करने वाले सब्सक्राइबर्स की कुल संख्या

- iv) सब्सक्राइबर द्वारा अला-कार्ट आधार पर चुने गए चैनलों के विवरण
 - v) पैकेज में चैनलों के पैकेजवार विवरण
 - vi) पैकेजवार सब्सक्राइबर सदस्य
 - vii) किसी विशेष चैनल अथवा पैकेज पर सब्सक्राइबर का चुनाव
 - viii) पिछले 2 वर्षों की अवधि के लिए उक्त संदर्भित सभी डाटा का इतिहास
9. एसएमएस तथा कैस प्रणाली पर कम-से-कम एक मिलियन समवर्ती सब्सक्राइबरों को निपटाने में समर्थ होने चाहिए।
 10. सीए तथा एसएमएस, दोनों ही प्रणालियाँ उत्कृष्ट संगठन की होनी चाहिए तथा इन्हें वर्तमान में अन्य पे-टेलीविजन सेवाओं द्वारा वर्तमान में प्रयोग में लाया जा रहा हो, जिनके पास वैश्विक पे-टीवी बाजार में न्यूनतम एक मिलियन सब्सक्राइबर हों।
 11. कैस प्रणाली प्रदाता किसी विशेष चैनल पर अथवा किसी विशेष पैकेज पर एक्टिवेशन का मासिक लॉग प्रदान करने में समर्थ होना चाहिए।
 12. एसएमएस मदवार बिल जैसे विषय-वस्तु की लागत, उपस्करों का किराया, कर आदि सृजित करने में समर्थ होना चाहिए।
 13. सीए तथा एसएमएस प्रणाली आपूर्तिकर्ता के पास भारत में तकनीकी क्षमता होनी चाहिए कि वह पूरे वर्ष के दौरान 24X7 आधार पर प्रणाली का अनुरक्षण कर सके।
 14. कैस एवं एसएमएस के पास ऐसे वीसी नम्बरों तथा एसटीबी नम्बरों को टैग तथा ब्लैकलिस्ट करने का प्रावधान होना चाहिए जो पूर्व में चोरी में शामिल हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वीसी अथवा एसटीबी की पुनः तैनाती न की जाए।"

एन. परमेश्वरन, प्रधान सलाहकार (बीएंडसीएस)

[विज्ञापन III/4/142/2008/असा.]

टिप्पणी 1.— प्रधान विनियम अधिसूचना सं० 8-26/2004-बीएंडसीएस दिनांक 10 दिसम्बर, 2004 द्वारा प्रकाशित हुए थे तथा इनमें बाद में अधिसूचना सं० 3-57/2005-बीएंडसीएस दिनांक 3 मार्च, 2005, सं० 11-13/2006-बीएंडसीएस दिनांक 24 अगस्त, 2006, सं० 6-4/2006-बीएंडसीएस दिनांक 34 सितम्बर, 2006 और सं० 4-54/2007-बीएंडसीएस दिनांक 3 सितम्बर, 2007 द्वारा संशोधन किए गए।

टिप्पणी 2.— व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन (पांचवां संशोधन) विनियम, 2009 के उद्देश्यों और कारणों का वर्णन करता है।

अनुबंध

व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमि

1. दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 प्रसारण और केबल सेवाओं के संबंध में अंतरसंयोजन के लिए विनियमक ढांचा प्रदान करने के उद्देश्य से 10 दिसम्बर, 2004 को जारी किया गया था। इन विनियमों को इसलिए जारी किया गया था ताकि टीवी चैनलों के विवरण सभी प्रसारकों के कंटेंट की गैर-भेदभावपूर्ण तरीके से एक्सेस प्राप्त कर सकें तथा सिगनलों को समाप्त किए जाने से पूर्व ग्रंथस्थिति किसी प्रसारक अथवा एमएसओ द्वारा सार्वजनिक नोटिस जारी करने को अधिदेशित किया जा सके ताकि उपभोक्ता अपने हितों का संरक्षण करने में समर्थ हो सकें।

2. इन विनियमों में इनके जारी किए जाने की तारीख से लेकर अब तक चार बार संशोधन किया जा चुका है। संशोधन विनियम विद्यमान उपबंधों के आशोधन और परिवर्धन के लिए तथा कुछ ऐसे नए मुद्दों के लिए जो उस समय तक विनियमों में शामिल नहीं किए गए थे, को शामिल करने के लिए 3 मार्च 2005, 24 अगस्त, 2006, 4 सितम्बर, 2006 तथा 3 सितम्बर, 2007 को जारी किए गए थे। कैस की अधिसूचना, डीटीएच तथा अन्य एड्रेसेबल प्रणालियों के संवर्धन के कारण प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्र में दिगत समय में होने वाले परिवर्तनों तथा अंतरसंयोजन विनियमों के क्रियान्वयन में हासिल किए गए अनुभूतियों के कारण ऐसे संशोधन अवश्य हो गए थे। हाल ही में, एड्रेसेबल तथा गैर-एड्रेसेबल प्लेटफार्मों से संबंधित कतिपय मुद्दों पर इन विनियमों में संशोधन करने पर विचार करने की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, एक संशोधन प्रक्रिया आरंभ की गई, जिसका आगे उल्लेख किया गया है।

परामर्श प्रक्रिया

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ट्राई अधिनियम, 1997 कहा गया है) की धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (ii), (iii) और (iv) में प्राधिकरण के लिए उपबंध है कि वह "(ii)सेवा प्रदाताओं के बीच अंतरसंयोजन के लिए निबंधन और शर्तें नियत करे," "(iii) विभिन्न सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी सामंजस्य और प्रभावी अंतरसंयोजन सुनिश्चित करे," तथा "(iv) सेवा प्रदाताओं के बीच दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने से प्राप्त हुए उनके राजस्व की साझेदारी की व्यवस्था को विनियमित करे"। ट्राई अधिनियम, 1997 की धारा 11 की उप-धारा (4) प्राधिकरण से अपेक्षा करती है कि वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते समय तथा इसके कृत्यों के निर्वहन में पारदर्शिता सुनिश्चित करे। तदनुसार, प्राधिकरण ने दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 का संशोधन करने से पूर्व एक परामर्श-प्रक्रिया आयोजित करने का निर्णय लिया।

3. परामर्श प्रक्रिया का प्रारंभ प्रसारण और केबल से संबंधित अंतरसंयोजन मुद्दों पर 15 दिसम्बर, 2008 को एक परामर्श-पत्र परिचालित करने के माध्यम से किया गया था जिसमें पणधारकों से टिप्पणियां मांगी गई थीं। 29 पणधारकों/प्रतिनिधियों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। परामर्श-पत्र में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर आगे विचार-विमर्श करने के लिए पणधारकों के प्रतिनिधियों के साथ 6 फरवरी, 2009 को कोलकाता में एक ओपन हाउस चर्चा भी आयोजित की गई थी। प्राधिकरण ने अंतरसंयोजन विनियमों में संशोधन के लिए संशोधन विनियम का मसौदा अपनी वेबसाइट पर 26 फरवरी, 2009 को जारी किया था ताकि पणधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की जा सकें। टिप्पणियां 7 मार्च, 2009 तक मांगी गई थीं। 9 पणधारकों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुईं। विनियमों को अंतिम रूप देते समय इन टिप्पणियों का ध्यान में रखा गया।

परामर्श के मुद्दे

4. परामर्श-पत्र में परामर्श के लिए उठाए गए मुद्दों का नीचे पुनः उद्धृत किया गया है।

क. एड्रेसेबल प्लेटफार्म के लिए अंतरसंयोजन

क1 क्या अंतरसंयोजन विनियम द्वारा प्रस्तावित किए गए सभी एड्रेसेबल प्रणालियों हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) प्रकाशित करने का अनिवार्य कर्तव्य जाना चाहिए तथा क्या ऐसे आरआईओ सभी एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए समान हाने चाहिए अथवा क्या किसी प्रसारक का भिन्न प्लेटफार्म के लिए भिन्न आरआईओ का प्रस्ताव करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

क2. क्या कोई ऐसी कार्य-पद्धति है जोकि गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए कंटेंट की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

क3. ऐसे न्यूनतम विनिर्देशन/शर्तें क्या होनी चाहिए कि कोई टीवी चैनल वितरण प्रणाली अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के समान निबंधनों पर सिगनलों की प्राप्ति करने में संतुष्टि प्रदान कर सके? क्या परामर्श-पत्र के अनुबंध में दर्शाए गए विनिर्देशन इस संबंध में पर्याप्त रहेंगे?

क4. यह सुनिश्चित करने तथा सत्यापित करने के लिए क्या कार्य-पद्धति होनी चाहिए कि अन्य एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के समान निबंधनों पर सिगनल प्राप्त करने का आशय रखने वाला कोई वितरण नेटवर्क एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति करे?

क5. गैर-कैस क्षेत्रों में हाइब्रिड केबल नेटवर्कों का ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए जो दोनों अर्थात्, एनालॉग (बिना एन्क्रिप्शन) तथा डिजिटल (एन्क्रिप्शन सहित) प्रकार की सेवाएं प्रदान करते हैं ?

क6. क्या "वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स" को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है तथा वह परिभाषा क्या होनी चाहिए?

क7. क्या प्रसारकों को गैर-वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए प्रसारकों को आरआईओ से भिन्न वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए सभी एड्रेसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ प्रकाशित करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए?

क8. क्या विनियम में संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्तावों (आरआईओ) के स्थान पर सभी एड्रेसेबल प्रणालियों हेतु संदर्भ अंतरसंयोजन करार (आरआईए) प्रकाशित करने के लिए अधिदेशित किया जाना चाहिए?

क9. क्या अंतरसंयोजन करारों के हस्ताक्षर के लिए विनिर्दिष्ट 45 दिन की समयावधि को उस समय घटा दिया जाना चाहिए जब आरआईओ को ऊपर दिए गए सुझाव के अनुसार आरआईए से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है?

क10. क्या विनियम में प्रसारकों को किसी एड्रेसेबल प्लेटफार्म में चैनलों की पैकेजिंग पर किसी प्रकार की सीमाएं अधिरोपित करने से विनिर्दिष्ट तौर पर प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए?

क11. क्या विनियम में प्रसारकों को किसी एड्रेसेबल प्लेटफार्म में चैनलों के मूल्य निर्धारण पर किसी प्रकार की सीमाएं अधिरोपित करने से विनिर्दिष्ट तौर पर प्रतिषिद्ध किया जाना चाहिए?

ख गैर-एड्रेसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन

ख1. क्या विनियम में गैर-एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ में निबंधन और शर्तें तथा वितरणों को निम्न रूप से शामिल करना निर्दिष्ट किया जाना चाहिए जैसाकि डीटीएच के लिए किया गया है?

ख2. गैर-एड्रेसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ में शामिल किए जाने के लिए क्या निबंधन और शर्तें तथा वितरण निर्दिष्ट किए जाने चाहिए?

ग. सामान्य अंतरसंयोजन मुद्दे

ग.1 क्या यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि इससे पूर्व कि कोई सेवा प्रदाता अंतरसंयोजन विनियमों के अधीन प्रदान किए गए लाभों/संरक्षणों का लाभ उठाने के लिए पात्र बने, उसे पहले यह सिद्ध करना होगा कि वह सेवा गुणवत्ता विनियमों के अंतर्गत यथालागू सभी अपेक्षाओं की पूर्ति करता है?

ग.2 क्या अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 की प्रयोज्यता को सीमित किया जाना चाहिए ताकि टीवी चैनलों के किसी वितरक को किसी प्रसारक से अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 के निबंधनों में ऐसे चैनलों के सिगनल प्राप्त करने से रोका जा सके, जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरकों द्वारा प्रसारक से कैरिज शुल्क की मांग की जा रही है?

ग.3 क्या कैरिज शुल्क की कतिपय विशेषताओं जैसे स्थायित्व, पारदर्शिता संभाव्यता और आवधिकता तथा साथ ही टीएएम/टीआरपी रेटिंग और कैरिज शुल्क के बीच संबंध को विनियमित किए जाने की आवश्यकता है?

ग.4 यदि हां, तो ऐसे विनियम की रीति क्या होनी चाहिए?

ग.5 क्या प्रसारकों और एमएसओ के बीच मानक अंतरसंयोजन करार को संशोधित किया जाना चाहिए ताकि एमएसओ, जिसे कैस-क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया है, कैस क्षेत्रों में एमएसओ से सहबद्ध केबल प्रचालकों को सिगनलों के कैरिज के लिए हिट्स प्रचालक की अवसंरचना का उपयोग करने में समर्थ हो सके?

ग.6 क्या प्राधिकरण द्वारा प्रसारकों तथा हिट्स प्रचालकों के बीच मानक अंतरसंयोजन करार को निर्दिष्ट किए जाने की आवश्यकता है तथा क्या यह मोटे तौर पर वैसा ही होना चाहिए जैसेकि कैस अधिसूचित क्षेत्रों में प्रसारकों और एमएसओ के बीच विनिर्दिष्ट किया गया है?

ग.7 यह सुनिश्चित करने के लिए और आगे क्या विनियामक उपाय किए जाने की आवश्यकता है कि डीटीएच प्रचालक सब्सक्राइबर्स के लिए छह माह का संरक्षण उपलब्ध कराने में समर्थ हैं, जैसाकि डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक तथा शिकायतों का निराकरण) विनियम, 2007 के खंड 9 के उप-खंड (1) में उपबंध किया गया है?

ग.8 इस उद्देश्य के लिए, क्या प्रसारकों के लिए अंतरसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख के पश्चात छह माह की अवधि के लिए डीटीएच प्रचालकों को सिगनल प्रदान करना जारी रखना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए ताकि डीटीएच प्रचालक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें?

ग.9 क्या ऐसा कोई अन्य विनियामक उपाय है जिसमें समान उद्देश्य की प्राप्ति हो सके?

घ. अंतरसंयोजन करारों का पंजीकरण

घ.1 क्या सभी अंतरसंयोजन करारों को लिखित में सीमित किया जाना अनिवार्य बनाया जाना चाहिए?

घ.2 क्या प्रसारकों/एमएसओ के लिए यह अनिवार्य बनाया जाना चाहिए कि वे केवल विधिवत रूप से लिखित अंतरसंयोजन करार करने के बाद ही टीवी चैनलों के किसी वितरक को सिगनल प्रदान करें?

घ3. क्या ऐसे टीवी चैनलों के वितरकों के लिए कोई विनियामक संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए जिन्होंने लिखित में अंतरसंयोजन करार नहीं किया है?

घ4. ऐसे कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की प्रति टीवी चैनलों के वितरकों को दी जा रही है?

घ5. क्या यथारिथाते, एमएसओ अथवा एलसीओ को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की प्रति सौंपना तथा इस संबंध में पावती प्राप्त करना प्रसारक की जिम्मेदारी होना चाहिए? क्या ऐसी ही जिम्मेदारी एमएसओ को भी दी जानी चाहिए जब वे अपने संबद्ध एलसीओ के साथ अंतरसंयोजन करार कर रहे हों?

परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

सभी एड्रसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ

5. अधिकांश प्रसारक सभी एड्रसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ रखने के पक्ष में थे। तथापि, कुछ प्रसारकों ने इस विचार का विरोध किया। टीवी चैनलों के सभी वितरक चाहते थे कि प्रसारक सभी एड्रसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ प्रकाशित करें। वैयक्तिक तथा उपभोक्ता समूहों ने भी सभी एड्रसेबल प्रणालियों के लिए आरआईओ को अवधारणा का पक्ष लिया। तथापि, सभी एड्रसेबल प्लेटफार्मों पर समान आरआईओ रखने के मुद्दे पर प्रसारकों के बीच सहमति नहीं थी। टीवी चैनलों के वितरकों में भी इस विषय पर मतभेद था।

एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशन

6. अधिकांश प्रसारकों का यह मत था कि एड्रसेबल प्रणालियों के लिए परामर्श-पत्र के साथ सलग्न विनिर्देशन अपर्याप्त हैं। टीवी चैनलों के वितरकों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद था। जबकि उपभोक्ता समूहों ने यह महसूस किया कि विनिर्देशन पर्याप्त हैं, व्यक्ति-विशेषों ने अनुलग्नक में दिए गए एड्रसेबल प्रणालियों के लिए विनिर्देशन को अपर्याप्त बताया।

वाणिज्यिक सब्सक्राइबर

7. अधिकांश सब्सक्राइबर्स ने सुझाव दिया कि "वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स" को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है। टीवी चैनलों के सभी वितरकों, जिनमें दो डीटीएच प्रचालक अपवाद थे, ने भी इस राय से सहमति व्यक्त की। दो डीटीएच प्रचालकों, जिन्होंने "वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स" को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता का विरोध किया था, ने सुझाव दिया कि वाणिज्यिक और आवासीय सब्सक्राइबर्स के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए। इन डीटीएच प्रचालकों द्वारा यह कहा गया कि किसी एड्रसेबल प्लेटफार्म के मामले में, प्रत्येक एवं हर सब्सक्राइबर को हिसाब में लिया जाता है तथा आवासीय एवं वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए। वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स सहित सभी प्रकार के सब्सक्राइबर्स को एड्रसेबल प्लेटफार्मों द्वारा सिगनलों की आपूर्ति के लिए समान दर और निबंधन एवं शर्तें लागू की जानी चाहिए। उपभोक्ता समूहों तथा व्यक्ति-विशेषों ने भी "वाणिज्यिक सब्सक्राइबर" को परिभाषित करने का पक्ष लिया। जहां तक वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए सभी एड्रसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ प्रकाशित करने के लिए प्रसारकों को अधिदेशित करने के मुद्दे का संबंध है, अधिकांश प्रसारक ऐसे संशोधन से सहमत थे। टीवी चैनलों के सभी वितरक, जिनमें दो डीटीएच प्रचालक अपवाद थे, भी यह चाहते थे कि प्रसारकों को वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए सभी एड्रसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ प्रकाशित करने के

लिए अधिदेशित किया जाए। दो डीटीएच प्रचालकों ने, जिन्होंने वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए ऐसे आरआईओ की आवश्यकता का विरोध किया था, सुझाव दिया कि वाणिज्यिक तथा आवासीय सब्सक्राइबर्स के बीच कोई विभेद नहीं होना चाहिए।

सभी एड्रसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन करार

8. इस प्रस्ताव का अधिकांश प्रसारकों द्वारा विरोध किया गया। दूसरी ओर, टीवी चैनलों के अधिकांश वितरकों ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। उपभोक्ता समूह तथा व्यक्ति-विशेषों ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है।

चैनलों की पैकेजिंग/मूल्य-निर्धारण पर निर्बंधन

9. सभी प्रसारकों ने एड्रसेबल प्लेटफार्मों पर पैकेजिंग सीमाएं अधिरोपित करने से प्रसारकों पर किसी प्रकार का प्रतिषेध लगाने का विरोध किया है। टीवी चैनलों के सभी वितरक ऐसा प्रतिषेध अधिदेशित करना चाहते थे। उपभोक्ता समूहों तथा वैयक्तिक पणधारकों ने भी ऐसे प्रतिषेध का पक्ष लिया है। एड्रसेबल प्लेटफार्मों पर मूल्य-निर्धारण निर्बंधन अधिरोपित करने से प्रसारकों पर प्रतिषेध के बारे में भी ऐसी ही टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं। तथापि, एक प्रसारक कंपनी एड्रसेबल प्लेटफार्मों में मूल्य-निर्धारण निर्बंधन अधिरोपित करने से प्रसारकों को रोकने की अवधारणा से सहमत थी। इस प्रसारक कंपनी ने यह बताया कि क्षेत्र में प्लेटफार्मों के मध्य कड़ी प्रतिस्पर्धा है, अतः बाजार की शक्तियों को प्लेटफार्मों द्वारा चैनलों के मूल्य-निर्धारण को अवधारित करने देना चाहिए तथा प्रसारकों को चैनलों के मूल्य-निर्धारण पर कोई निर्बंधन अधिरोपित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

गैर-एड्रसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन

10. गैर-कैस टैरिफ आदेश के आठवें संशोधन को माननीय टीडीसैट ने 2006 की अपील संख्या 9(सी) तथा 2007 की अपील संख्या 10(सी), 11(सी), 12(सी), 13(सी) और 15(सी) में दिनांक 15 जनवरी, 2009 को दिए गए अपने निर्णय में निरस्त कर दिया है। तदनुसार, प्राधिकरण ने वर्तमान में गैर-एड्रसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन से संबंधित मुद्दों की जांच करना उपयुक्त नहीं समझा है क्योंकि गैर-एड्रसेबल प्लेटफार्मों के लिए अंतरसंयोजन से संबंधित प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य अंतरसंयोजन विनियमों के उपबंधों के साथ टैरिफ आदेश के उपबंधों का सामंजस्य करना था।

सेवा गुणवत्ता विनियमों का अनुपालन

11. अधिकांश पणधारकों ने इस अवधारणा का पक्ष लिया है कि अंतरसंयोजन विनियमों के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभों/संरक्षणों का उपयोग करने के लिए सेवा प्रदाता के पात्र बनने से पूर्व उन्हें यह सिद्ध करना होगा कि वह सेवा गुणवत्ता विनियमों के अंतर्गत यथालागू समस्त अपेक्षाओं की पूर्ति करता है। तथापि, इसका विरोध दो डीटीएच प्रचालकों द्वारा इस आधार पर किया गया है कि ऐसा कोई कदम अंतरसंयोजन तथा कंटेंट के सुचारु वितरण के लाभ को समाप्त करेगा, और यह अव्यक्ति का कदम हो सकता है, तथा यह कि दो मुद्दों का आपस में जोड़ने से केवल संदेह की स्थिति ही पैदा होगी और यह प्रसारक को गैर-भदभाटपूर्ण आधार पर सेवा प्रदाता को सिगनल प्रदान न करने का बहाना बनाने का अवसर प्रदान करेगा।

कैरिज शुल्क - अंतरसंयोजन विनियम के खंड 3.2 की प्रयोज्यता को निर्बंधित करना

12. सभी प्रसारकों ने यह मांग की है कि "मस्ट प्रोवाइड" उपबंध को केवल उन्हीं चैनलों के लिए सीमित किया जाना चाहिए जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरक द्वारा कैरिज शुल्क की मांग की

जा रही है। दूसरी ओर, टीवी चैनलों के सभी वितरकों ने ऐसी किसी सीमा का विरोध किया है। उपभोक्ता समूहों ने प्रसारकों के मतों से सहनति व्यक्त की है तथा वैयक्तिक पणधारकों में इस मुद्दे पर मतभेद है।

कैरिज शुल्क - विनियम की आवश्यकता

13. टीवी चैनलों के वितरकों ने कैरिज शुल्क के लिए किसी भी विनियम का विरोध किया है। उनके द्वारा इस बात का आशय व्यक्त किया गया है कि यह मुद्दा काफी जटिल और संश्लिष्ट है तथा कैरिज शुल्क को विनियमित करने के लिए कोई भी सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता है। यह उल्लेख किया गया है कि अवसंरचना लागू और विलयन सब्सक्रिप्शन राजस्वों के बीच मेल न होने के कारण एड्रसेबल प्लेटफार्म का भरी प्रचालनात्मक घाटा होता है। इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि किसी प्रसारक विज्ञापन राजस्व विनियमित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार कैरिज शुल्क का निर्णय बाजारी शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए क्योंकि दोनों घनिष्टता से जुड़े हैं। दूसरी ओर, प्रसारकों ने कैरिज शुल्क पर कुछ विनियमों की मांग की है। एक प्रसारक ने यह सुझाव दिया कि विनियामक एक पृथक परामर्श प्रक्रिया के माध्यम से तथा एक मुख्य परामर्श समिति, जिसमें सभी पणधारक शामिल हों, के माध्यम से इस उद्देश्य को प्राप्त करे और एक संतुलित तंत्र का विकास करे।

कैस क्षेत्रों के लिए मानक अंतरसंयोजन करार - हिट्स प्रचालक अवसंरचना का प्रयोग

14. टीवी चैनलों के सभी वितरकों ने कैस क्षेत्रों के लिए मानक अंतरसंयोजन करारों में संशोधन की मांग की ताकि एमएसओ सिग्नलों के लिए हिट्स प्रचालकों की अवसंरचना का उपयोग कर सकें। उपभोक्ता समूह ने भी इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। इस मुद्दे पर प्रसारकों में मतभेद था। प्रसारकों और हिट्स प्रचालकों के बीच मानक अंतरसंयोजन करार विनिर्दिष्ट करने की आवश्यकता के मुद्दे पर सभी पणधारकों के समूह अर्थात् प्रसारक, टीवी चैनलों के वितरक और उपभोक्ताओं के बीच मतभेद था।

डीटीएच सब्सक्राइबर्स के लिए टैरिफ संरक्षण

15. प्रसारक डीटीएच प्रचालकों को उनके दायित्वों के निर्वहन हेतु समर्थ बनाने के लिए अंतरसंयोजन करार की समाप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि के लिए डीटीएच प्रचालकों को सिग्नल देना जारी रखने की प्रसारकों पर थोपी गई किसी प्रकार की बाध्यता के खिलाफ हैं। डीटीएच प्रचालक चाहते थे कि ऐसी कोई व्यवस्था शुरू की जाए। इस मुद्दे पर एमएसओ के बीच मतभेद था और उपभोक्ता समूह प्रसारकों की बात से सहमत थे।

लिखित अंतरसंयोजन करार को अनिवार्य बनाना

16. लगभग सभी पणधारकों ने यह सुझाव दिया कि सभी अंतरसंयोजन करारों को लिखित रूप देना अनिवार्य बनाया जाए। एक प्रसारक ने इस आधार पर इस प्रस्ताव का विरोध किया इस संबंध में कोई विनियम नहीं होना चाहिए। एक डीटीएच प्रचालक ने यह टिप्पणी की कि देश के कानून के अनुसार लिखित अंतरसंयोजन करारों का होना जरूरी नहीं है (संविदा अधिनियम के अनुसार) और इसलिए ऐसी अपेक्षा स्थापित कानूनी सिद्धांतों के विपरीत होगी। एक अन्य डीटीएच प्रचालक का यह मत था कि अंतरसंयोजन करार करने का तरीका एक प्रचालनात्मक विषय है और इसका निर्णय बाजारी शक्तियों को करने देना चाहिए।

17. अधिकांश पणधारक इस पक्ष में थे कि प्रसारक/एमएसओ के लिए यह अनिवार्य हो कि वे विधिवत रूप से एक लिखित अंतरसंयोजन करार निष्पन्न करने के बाद ही सिग्नल उपलब्ध कराएं। तथापि, यह राय भी व्यक्त की गई कि निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने के बाद एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पन्न करने का शपथ-पत्र देने पर सिग्नल उपलब्ध कराए जाएं। एक पणधारक ने यह भी कहा कि कभी-कभी किसी औपचारिक करार के बिना न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में सिग्नल उपलब्ध कराए जाते हैं।

18. अधिकांश पणधारकों ने लिखित अंतरसंयोजन करार न करने वाले टीवी चैनलों के वितरकों से विनियामक संरक्षण वापस लेने की वकालत की। इसी प्रकार, एमएसओ/एलसीओ को लिखित करार की प्रतियां सौंपने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के मुद्दे पर कुछ पणधारक यह चाहते थे कि इसके लिए प्रसारकों/एमएसओ को जिम्मेदार माना जाए।

द्वितीय चरण की परामर्श प्रक्रिया के दौरान प्राप्त प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

19. एक एमएसओ तथा एक डीटीएच प्रचालक ने सुझाव दिया कि आईपीटीवी की परिभाषा को अंतरसंयोजन विनियमों में अंतर्विष्ट किया जाना चाहिए क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश 8 सितम्बर, 2008 को पहले ही जारी कर दिए हैं।

20. ऐसे मामलों में, जहां कैरिज शुल्क की भी मांग की जा रही है, अंतरसंयोजन विनियमों के खंड 3.2 को प्रयोज्यता को निर्बंधित करने के मुद्दे पर दो एमएसओ ने प्रस्तावित संशोधन का विरोध किया। एक डीटीएच प्रचालक तथा एक एमएसओ ने सुझाव दिया कि ऐसे किसी निर्बंधन द्वारा वितरकों को स्थापन प्रभार प्रभारित करने से नहीं रोका जाना चाहिए।

21. लिखित करार को अधिदेशित करने वाले प्रस्तावित करारों का एक प्रसारक द्वारा स्वागत किया गया, जबकि अन्य प्रसारकों ने यह कहते हुए प्रस्ताव का विरोध किया कि ऐसी कोई शर्त प्रसारकों पर वाणिज्यिक लागत अधिरोपित करेगी। एक डीटीएच प्रचालक ने संविदा अधिनियम का हवाला दिया तथा यह कहा कि संविदा अधिनियम के अनुसार लिखित करार अनिवार्य नहीं है। एक डीटीएच प्रचालक तथा एक एमएसओ ने इंगित किया कि कभी-कभी सिग्नल न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में उपलब्ध कराए जाते हैं तथा प्रस्तावित संशोधन में ऐसे मामलों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

22. प्रस्तावित अधिनियम, जिसमें प्रसारकों तथा एमएसओ से अपेक्षा की गई है कि वे हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति एमएसओ/कैबल प्रचालकों को सौंपे, का एक प्रसारक द्वारा विरोध किया गया। दो पणधारकों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि, यथा-स्थिति, प्रसारकों, एमएसओ अथवा एचआईसीटीएस प्रचालकों द्वारा हस्ताक्षरित करारों की प्रतियां सौंपे जाने के लिए एक समय-सीमा निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

23. दो पणधारकों ने प्रसारकों द्वारा डीटीएच प्रचालकों के लिए संशोधित आरआईओ जारी करने के लिए समय-सीमा निर्दिष्ट करने के लिए विनियम 13.2क में संशोधनों का सुझाव दिया है। सात दिन की समय-सीमा सुझाई गई है।

24. वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स को सिगनलों की आपूर्ति के लिए डीटीएच प्रचालकों को समर्थ बनाने वाले प्रस्तावित संशोधनों का एक प्रसारक को छोड़कर सभी पणधारकों द्वारा स्वागत किया गया है, जिसने संशोधन का विरोध किया है और यह कहा है कि अपने हितों के संरक्षण के लिए सब्सक्राइबर्स के पास मोलाभाव करने की पर्याप्त शक्ति विद्यमान है। एक पणधारक ने वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स को सिगनलों की आपूर्ति के लिए डीटीएच प्रचालकों को समर्थ बनाने वाले प्रस्ताव का स्वागत किया है, लेकिन साथ ही आरआईओ के मामले में आवासीय और वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के बीच किसी विभेद का विरोध किया है।

25. वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए भिन्न आरआईओ के बारे में प्रस्तावित संशोधन का एक प्रसारक द्वारा विरोध किया गया है। प्रसारक ने टिप्पणी की है कि यदि ऐसा कोई विनियम बनाया ही जाना है, तो विभिन्न वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स के लिए विभिन्न आरआईओ की अनुमति दी जानी चाहिए। कुछ अन्य पणधारकों ने टिप्पणी की है कि विभिन्न एड्रसेबल प्रणालियों के लिए विभिन्न आरआईओ की अनुमति दिया जाना एक स्वागत योग्य कदम है।

26. दो पणधारकों ने एड्रसेबल प्रणालियों हेतु प्रसारकों द्वारा संशोधित आरआईओ जारी करने के लिए समय-सीमाएं निर्दिष्ट करने के लिए विनियम 13.2ख.1 में संशोधनों का सुझाव दिया है। पन्द्रह दिन की समय-सीमा सुझाई गई है।

दूरसंचार (प्रसारण और केबल सेवाएं) अंतरसंयोजन विनियम, 2004 में संशोधन करने का तर्काधार

27. प्राधिकरण ने यह नोट किया कि प्रौद्योगिकी उन्नयन से आगामी वर्षों में टीवी चैनलों के वितरण हेतु एड्रसेबल प्रणाली के बाजार-हिस्से में वृद्धि होगी। डीटीएच के अलावा, हिट्स और आईपीटीवी प्लेटफॉर्म पहले से पे-टीवी बाजार में मौजूद हैं। देश के विभिन्न भागों में केबल टीवी नेटवर्क के डिजिटलीकरण और स्वैच्छिक कैस की शुरुआत भी हो चुकी है। अतः प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि अंतरसंयोजन विनियम एड्रसेबल प्रणालियों के लिए अंतरसंयोजन करार में सहायक बनें। इसके अलावा, अधिकांश पणधारक सभी एड्रसेबल प्लेटफॉर्मों के लिए आरआईओ के पक्ष में हैं तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रसारकों द्वारा सभी एड्रसेबल प्लेटफॉर्मों (कैस अधिसूचित क्षेत्रों में केबल सेवाओं को छोड़कर) के लिए आरआईओ प्रकाशित करना अधिदेशित किया है। इसके साथ-साथ प्राधिकरण ने प्रसारकों को विभिन्न एड्रसेबल प्रणालियों के लिए विभिन्न आरआईओ रखने की अनुमति दे दी है। प्रसारकों को यह नम्यता विभिन्न एड्रसेबल प्रणालियों की विभिन्न विशेषताओं के आधार पर अपने आरआईओ से परिचित होने हेतु दी गई है। विनियमों में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सेवा (आईपीटीवी) की परिभाषा अंतःस्थापित की गई है क्योंकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 8 सितम्बर, 2008 को आईपीटीवी सेवाओं के प्रावधान के लिए दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं तथा अनेक सेवा प्रदाताओं ने अपनी आईपीटीवी सेवाएं पहले ही क्रियान्वित कर दी हैं।

28. प्राधिकरण यह तथ्य भी स्वीकार करता है कि किसी एड्रसेबल प्रणाली के कतिपय न्यूनतम विनिर्देशनों को अपफ्रंट में विनिर्दिष्ट किए जाने की जरूरत है ताकि इस संबंध में प्रसारकों तथा टीवी चैनलों के वितरकों के बीच के विवाद को कम किया जा सके। प्राधिकरण ने एड्रसेबल प्रणालियों के लिए न्यूनतम विनिर्देशनों (सूक्ष्म आशोधनों के साथ) को अपनाने का निर्णय लिया है जिन्हें पूर्व में डिजिटलीकरण और स्वैच्छिक कैस लागू करने के मद्दों पर विचार करने हेतु ट्राई, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, प्रसार भारती, प्रसारकों, एमएसओ, डीटीएच प्रचालकों, केबल प्रचालक/वितरक संघों और उपभोक्ता संगठनों के सदस्यों से मिलकर प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विशेषज्ञ समूह द्वारा संस्तुत किया गया है। ये विनिर्देशन विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुबंध 'ग' के रूप में संलग्न हैं। इसके अलावा, जहां पर प्रचालक का यह मत है कि टीवी चैनलों के वितरक द्वारा तैनात एड्रसेबल प्रणाली न्यूनतम विनिर्देशनों को पूरा नहीं करती है वहां ऐसी एड्रसेबल प्रणाली की लेखा-परीक्षा करने के लिए एक तंत्र की व्यवस्था की गई है।

29. प्राधिकरण ने गैर-कैस क्षेत्रों में हाइब्रिड केबल नेटवर्क, जो दोनों प्रकार की सेवाएं अर्थात् एनालॉग (बिना एंक्रिप्शन) एवं डिजिटल (एंक्रिप्शन सहित) प्रदान करता है, के संबंध में विशेष विनियम निर्धारित न करने का निर्णय लिया चूंकि अंतरसंयोजन विनियमों में एड्रसेबल के साथ-साथ गैर-एड्रसेबल प्रणालियों का भी ध्यान रखा जाता है। पक्ष वाणिज्यिक बातचीत के माध्यम से इसका परिष्कृत विवरणों का आकलन कर सकते हैं।

30. प्राधिकरण ने यह भी नोट किया कि कई प्रसारकों द्वारा प्रकाशित आरआईओ डीटीएच प्रचालकों के रिहायशी सब्सक्राइबर्स से भिन्न सब्सक्राइबर्स को अपनी सेवाएं उपलब्ध कराने से रोकता है। प्राधिकरण का यह मत है कि ऐसी कोई शर्त डीटीएच प्रचालकों को कई ऐसे सब्सक्राइबर्स को सेवाएं देने से रोकती है जो उनकी सेवाएं लेने के इच्छुक हैं। इसके साथ-साथ, प्रसारकों के हितों की भी रक्षा किए जाने की जरूरत है। तदनुसार, प्राधिकरण ने प्रसारकों को, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किसी डीटीएच प्रचालक को वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स सहित किसी भी श्रेणी के सब्सक्राइबर्स को उसकी डायरेक्ट-टु-होम सेवा उपलब्ध न कराने को बाध्य करने से प्रतिषिद्ध किया है। इसके साथ-साथ प्रसारकों को समय-समय पर यथासंशोधित दूरसंचार (प्रसारण और केबल) सेवाएं (दूसरा) टैरिफ आदेश, 2004 के खंड 2 के उप-खंड (च) की मद (ii) में सूचीबद्ध विशेष वाणिज्यिक सब्सक्राइबर्स को डीटीएच प्रचालकों द्वारा सिग्नल देने हेतु एक पृथक संदर्भ अंतरसंयोजन प्रस्ताव (आरआईओ) देने की अनुमति दी गई है। ये उपबंध अन्य एड्रसेबल प्लेटफार्मों हेतु आरआईओ पर भी लागू हैं।

31. प्राधिकरण ने एड्रसेबल प्रणालियों के लिए संदर्भ अंतरसंयोजन करार (आरआईए) को अधिदेशित न करने का निर्णय लिया है। इसके स्थान पर, यह महसूस किया गया है कि प्राधिकरण द्वारा आरआईओ के महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तों को निर्दिष्ट किया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आरआईओ में ऐसा कोई भी उपबंध नहीं है जो विनियमों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्यों के विपरीत है। प्राधिकरण ने यह महसूस किया कि आरआईओ के स्थान पर आरआईए को अधिदेशित किए जाने की जरूरत नहीं है चूंकि प्राधिकरण महत्वपूर्ण निबंधन और शर्तें पहले ही निर्दिष्ट की जा चुकी हैं।

32. प्राधिकरण ने यह सुनिश्चित करने के लिए विनियम 13.2क.11 में संशोधन किया है कि डीटीएच प्रचालकों और अन्य एड्रसेबल प्लेटफार्मों के पास किसी प्रसारक से चैनलों की पैकेजिंग के

संबंध में पूरी नम्यता हो। जहां तक एड्रसेबल प्लेटफार्मों पर चैनलों पर मूल्य-निर्धारण संबंधी निर्बंधन लगाने का संबंध है, प्राधिकरण का यह मत है कि यह एक वाणिज्यिक मुद्दा है जिसे प्रसारक और टीवी चैनलों के वितरक परस्पर बैठकर सुलझाएँ।

33. प्राधिकरण ने इस मुद्दे का विस्तार से विश्लेषण किया है कि क्या यथालागू सेवा-गुणवत्ता विनियमों के अंतर्गत सभी अपेक्षाओं की पूर्ति को किसी सेवा प्रदाता के लिए अंतरसंयोजन विनियमों के अंतर्गत दिए गए लाभ/संरक्षण का फायदा लेने हेतु एक पूर्व-शर्त बनाया जाए। प्राधिकरण ने ऐसे किसी प्रावधान को शुरू न करने का निर्णय लिया है क्योंकि यह महसूस किया गया कि ऐसे किसी प्रावधान से मुकदमों की संख्या में वृद्धि हो सकती है।

34. प्राधिकरण ने इस अवस्था में निम्न कारणों से कैरिज शुल्क के विनियमन के विरुद्ध निर्णय लिया :-

- (क) कैरिज शुल्क बाजार आधारित प्रक्रिया है और कैरिज शुल्क के स्तर का निर्धारण बाजारी शक्तियों द्वारा किया जाता है। कैरिज शुल्क वितरण प्लेटफार्मों की क्षमता संबंधी बाधाओं के कारण मांग-आपूर्ति में असमानता का प्रमुख परिणाम है।
- (ख) एक प्रसारक द्वारा कैरिज/स्थापन/तकनीकी शुल्क की अदायगी प्रसारक को बढ़े हुए विज्ञापन राजस्व के माध्यम से होने वाले परिकल्पित लाभ से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। यह संबद्धता टीएएम शहरों (ऐसे शहर जहां रेटिंग एगेंसियों ने प्रतिदर्श कुटुम्बों में अपने मीटर उपकरण लगा रखे हैं) में कैरिज शुल्क के अधिकतम स्तर द्वारा प्रकट होती है। अतः विज्ञापन राजस्व को विनियमित किए बिना कैरिज शुल्क का विनियमन नहीं किया जा सकता है।
- (ग) कैरिज शुल्क की वसूली की प्रतिपूर्ति अंततः विज्ञापनदाताओं से टीवी चैनलों पर उच्च विज्ञापन प्रभारों के माध्यम से हो जाती है। तथापि, इस संबंध में अभी तक किसी विज्ञापनदाता ने कोई आपत्ति नहीं की है।
- (घ) देश में प्रसारण और केबल टीवी बाजार में अपर्याप्त डिजिटलीकरण के फलस्वरूप ही मूलतः बाजार में कैरिज शुल्क का प्रादुर्भाव हुआ है। टीवी चैनलों के कुछ वितरकों ने यह विचार भी व्यक्त किया है कि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए कैरिज शुल्क की वास्तव में आवश्यकता है। इसे सीलिंग या कैरिज पर एक प्रभार विनिर्दिष्ट करके विनियमित करने का कोई प्रयास डिजिटल नेटवर्कों की तैनाती को घीसा कर देगा।
- (ङ) कैरिज शुल्क की अदायगी प्रायः नकद या वस्तु के रूप में की जाती है (हेड एंड हेतु उपकरण, विदेशी दौरा, उपहार आदि)। इसके अतिरिक्त, कैरिज शुल्क लेने वाले टीवी चैनलों के कई वितरक छोटे प्रचालक हैं और उनके खाते सांविधिक लेखा-परीक्षा के अध्वधीन नहीं हैं। इसलिए कैरिज शुल्क के किसी विनियमन से यह निश्चित है कि यह एक अत्यंत त्रुटिपूर्ण विनियम होगा। इसके अलावा, कैरिज शुल्क विनियमन में प्रवर्तन संबंधी समस्याएं आने की संभावना है जिससे बाजार में अन्य विकृतियां आएंगी।
- (च) यदि कैरिज शुल्क के लिए कोई सीलिंग निर्धारित की जाती है तो यह संभावना है कि और अधिक चैनल, उपलब्ध चैनल स्लॉट की संख्या की तुलना में अधिकतम अनुमत कैरिज शुल्क की अदायगी करने के इच्छुक हों। ऐसी स्थिति में किस चैनल को कैरी करना है उसके चयन के परिणामस्वरूप पुनः गुप्त सौदे होंगे।

- (छ) टीवी चैनलों के कुछ वितरकों का अन्य व्यवसाय भी है (जैसे समाचार-पत्र, रेडियो स्टेशन, मनोरंजन पार्क आदि)। यदि टीवी चैनलों के ऐसे वितरक अन्य कंपनियों द्वारा एक समूह के भीतर बेचे गए अन्य माल या सेवाओं के लिए अदायगी के रूप में कैरिज शुल्क वसूलना शुरू कर दें, तो कैरिज शुल्क को विनियमित करना व्यावहारिक रूप से असंभव होगा।
- (ज) कैरिज शुल्क किसी चैनल की लोकप्रियता से भी संबंधित है, जिसका निर्धारण बाजार करता है। ऐसे परिदृश्य में, विविध प्रकार की लोकप्रियता वाले चैनलों के लिए विनियम के माध्यम से एक कैरिज शुल्क प्रणाली निर्धारित करना काफी मुश्किल होगा।
- (झ) कैरिज शुल्क पर कोई विनियम लागू करने हेतु कोई उपयुक्त तंत्र नहीं है।

35. तथापि, प्राधिकरण ने उन चैनलों में इसकी प्रयोज्यता को सीमित करने हेतु विनियम 3.2 में संशोधन किया है जिनके संबंध में टीवी चैनलों के वितरक द्वारा अपने वितरण प्लेटफार्म पर चैनलों के कैरिज के लिए प्रसारक से किसी शुल्क की मांग की जा रही है। ऐसा यह सुनिश्चित करने हेतु किया गया है कि प्रसारकों को विनियम 3.2 के संदर्भ में उनके चैनल की आपूर्ति करने और न ही उन्हें उस चैनल हेतु कैरिज शुल्क की अदायगी हेतु बाध्य किया जाए। यह संशोधन टीवी चैनलों के वितरक को विनियम 3.2 का दुरुपयोग करने से रोकने हेतु किया गया है। तथापि, यह संशोधन टीवी चैनलों के वितरक को उस मामले में किन्हीं अन्य प्रसारकों के चैनलों की तुलना में किसी प्रसारक के उसके वितरण प्लेटफार्म में चैनल के स्थापन हेतु शुल्क वसूलने से नहीं रोकता है, यदि प्रसारक उस चैनल को एक फ्रीक्वेंसी-विशेष पर रखना चाहता हो।

36. दर्शक संख्या बढ़ाने तथा उनके चैनल(लों) के राजस्व में वृद्धि करने के लिए उनके चैनल (लों) को अपेक्षित फ्रीक्वेंसी/टियर/पैकेज पर रखने के लिए प्रसारकों द्वारा टीवी चैनलों के वितरकों को "स्थापन शुल्क" का भुगतान किया जाता है। स्थापना शुल्क "कैरिज शुल्क" से भिन्न है तथा प्राधिकरण द्वारा इन दो निबंधनों को परिभाषा खंड में परिभाषित किए जाने से इस पहलू को विशेष रूप से मान्यता प्रदान की गई है। संशोधन का आशय केवल कैरिज शुल्क के मुद्दे का समाधान करना है, न कि स्थापन शुल्क का, जोकि बाजार की शक्तियों तथा प्रसारक(कों) और वितरक(कों) के बीच पारस्परिक बातचीत द्वारा विनियंत्रित किया जाता है।

37. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने हिट्स प्लेटफार्मों के लिए लाइसेंसिंग नीति अभी तक जारी नहीं की है। ऐसे परिदृश्य में, प्राधिकरण वर्तमान में हिट्स प्रचालकों के लिए कोई विनियम बनाने को उचित नहीं मानता है। तदनुसार, संशोधन विनियम में हिट्स संबंधी मुद्दों का समाधान नहीं किया गया है।

38. प्राधिकरण यह महसूस करता है कि डीटीएच सब्सक्राइबर्स को छह माह का टैरिफ संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य को डीटीएच प्रचालकों द्वारा प्रसारकों के साथ उपयुक्त अंतरसंयोजन करार करके प्राप्त किया जा सकता है। इसके अलावा, डीटीएच प्रचालकों के पास यह भी विकल्प है कि वे ऐसे पैकेज में नए सब्सक्राइबर्स का नामांकन बंद कर दें जिनमें से आगामी छह महीने में चैनल हटाया जाना है। तदनुसार, प्राधिकरण ने इस अवस्था में सब्सक्राइबर को छह महीने का टैरिफ संरक्षण देने में डीटीएच प्रचालकों की सहायता हेतु कोई विनियामक उपाय शुरू न करने का निर्णय

लिया जैसाकि डायरेक्ट-टु-होम प्रसारण सेवाएं (सेवा गुणवत्ता के मानक और शिकायतों का निराकरण) विनियम, 2007 के खंड 9 के उप-खंड (1) में उपबंधित है।

39. प्राधिकरण की यह राय है कि एक लिखित अंतरसंयोजन करार न होने से काफी विवाद होता है। इसके अतिरिक्त, अंतरसंयोजन करार रजिस्टर में मौखिक करारों को रिकार्ड करना संभव नहीं है। इस क्षेत्र में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर प्राधिकरण ने यह अधिदेशित किया है कि पे-चैनलों के प्रसारक या टीवी चैनलों के वितरक जैसे मल्टी सिस्टम प्रचालक या हैडएंड इन द स्काई प्रचालक एक लिखित अंतरसंयोजन करार किए बिना टीवी चैनलों के किसी वितरक का टीवी चैनल सिग्नल उपलब्ध नहीं कराएंगे। इसके अलावा, टीवी चैनलों के वितरक को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति सौंपने और इसकी पावती लेने की जिम्मेदारी पे-चैनलों के प्रसारकों को दी गई है। इसी तरह की जिम्मेदारी मल्टी सिस्टम प्रचालकों को दी गई है कि वे केबल प्रचालकों को हस्ताक्षरित अंतरसंयोजन करार की एक प्रति सौंपें और इस संबंध में पावती लें।

40. प्राधिकरण ने किसी अंतरसंयोजन करार में शामिल किए जाने के लिए न्यूनतम आवश्यक विवरण निर्दिष्ट नहीं किए हैं। अतः दो सेवा प्रदाताओं द्वारा हस्ताक्षर की गई टर्म-शीट ही इन विनियमों की अपेक्षा के अनुसार अनुपालन के लिए पर्याप्त होगी। अतः सिग्नलों की आपूर्ति को टर्म-शीट हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात प्रारंभ किया जा सकता है। विस्तृत करार बाद में हस्ताक्षरित किया जा सकता है।

41. मौखिक अंतरसंयोजन करारों की प्रथा को रोकने के लिए विनियम 4.1 के उपबंधों में भी संशोधन किया गया है ताकि केवल उन टीवी चैनलों के वितरकों, जिन्होंने लिखित अंतरसंयोजन करार किए हैं, को कोई नोटिस दिए बिना विच्छेदन से विनियामक संरक्षण मिले।

42. तथापि, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि कई बार न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में टीवी चैनलों के वितरकों को सिग्नल दिए जाते हैं, अपवादस्वरूप एक व्यवस्था की गई है जिसमें टीवी चैनलों के प्रसारकों/वितरकों (एमएसओ/हिट्स प्रचालकों) को लिखित करार किए बिना टीवी चैनलों के वितरकों (एलसीओ) को सिग्नल देने का प्रावधान है।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2009

The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulations, 2009

(No. 4 of 2009)

F. No. 3-21/2009-B&CS.—In exercise of the powers conferred by section 36, and by sub-clauses (ii), (iii), (iv) and (v) of clause (b) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), read with notification of the Government of India, in the Ministry of Communication and Information Technology (Department of Telecommunication) No.39,-----

(a) issued, in exercise of the powers conferred upon the Central Government under clause (d) of sub-section (1) of section 11 and proviso to clause (k) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, and

(b) published under notification No. S.O.44 (i.) and 45 (E) dated the 9th January, 2004 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4,

the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), namely:-

1. (1) These regulations may be called the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulations, 2009.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004 (13 of 2004), (hereinafter referred to as the principal regulations), -----

(a) sub-clause (ia) shall be renumbered as sub-clause (ib);

(b) after sub-clause (i), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(ia) “**carriage fee**” means any fee paid by a broadcaster to a distributor of TV channels, for carriage of the channels or bouquets of channels of that broadcaster on the distribution platform owned or operated by such distributor of TV channels, without specifying the placement of various channels of the broadcaster vis-à-vis channels of other broadcasters;”

(c) after sub-clause (l), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(la) “**Internet Protocol television service**” means delivery of multi channel TV programmes in addressable mode by using Internet Protocol over a closed network of one or more service providers;”

(d) sub-clause (mc) shall be renumbered as sub-clause (md);

(e) after sub-clause (mb), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(mc) “**placement fee**” means any fee paid by a broadcaster to a distributor of TV channels, for placement of the channels of such broadcaster vis-à-vis channels of other broadcasters on the distribution platform owned or operated by such distributor of TV channels;”.

3. In regulation 3 of the principal regulations, -----

(a) after the second proviso to sub-regulation 3.2, the following proviso shall be inserted, namely :-

“Provided also that the provisions of this sub-regulation shall not apply in the case of a distributor of TV channels, who seeks signals of a particular TV channel from a broadcaster, while at the same time demanding carriage fee for carrying that channel on its distribution platform.”.

(b) the Explanation after the third proviso so inserted in sub-regulation 3.2 shall be numbered as Explanation 1;

(c) after Explanation 1 so numbered, the following explanation shall be inserted, namely:-

“Explanation 2. The stipulation of “placement frequency” or “package/tier” by the broadcaster from whom the signals have been sought by a distributor of TV channels, as a “pre-condition” for making available signals of the requested channel(s) shall also amount to imposition of unreasonable terms.”

4. In regulation 4 of the principal regulations,---

(a) in the first proviso to sub-regulation 4.1, for the words “an agreement, written or oral”, the words “a written agreement” shall be substituted;

(b) in the second proviso to sub-regulation 4.1, for the words “agreement, written or oral,” the words “written agreement” shall be substituted;

5. In the principal regulations, after regulation 4, the following regulations shall be inserted, namely:-

“4A. Interconnection Agreements to be in writing.

4A.1 It shall be mandatory for the broadcasters of pay channels and distributors of TV channels to reduce the terms and conditions of all their interconnection agreements to writing.

4A.2 No broadcaster of pay channels or distributor of TV channels, such as multi system operator or headend in the sky operator, shall make available signals of TV channels to any distributor of TV channels without entering into a written interconnection agreement.

4A.3 Nothing contained in regulations 4A.1 or 4A.2 shall apply to any supply of signals or continuance of supply of signals of TV channels by a broadcaster or distributor of TV channels, such as multi system operator or headend in the sky operator, in pursuance of or in compliance with any order or direction or judgment of any court or tribunal, including any order or direction or judgment of any court or tribunal on any proceeding pending before such court or tribunal.

4A.4 It shall be the responsibility of every broadcaster of pay channels who enters into an interconnection agreement with a distributor of TV channels to hand over a copy of signed interconnection agreement to such distributor of TV channels and obtain an acknowledgement in this regard within a period of 15 days from the date of execution of the agreement and, similarly, it shall be the responsibility of every multi system operator or headend in the sky operator, as the case may be, who enters into an interconnection agreement with a cable operator to hand over a copy of signed interconnection agreement to such cable operator and obtain an acknowledgement in this regard within a period of 15 days from the date of execution of the agreement.”.

6. In regulation 13.2A of the principal regulations, -----

(a) for regulation 13.2A.1, the following regulation shall be inserted, namely:-

“13.2A.1 Every broadcaster, providing broadcasting services before the date of commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009) and continues to provide such services after such commencement shall, within thirty days from the date of such commencement, intimate to all the direct to home operators existing on that date and coming into existence within the said period of thirty days, its Reference Interconnect Offer specifying, *inter-alia*, the technical and commercial terms and conditions for interconnection for the direct to home platform, including the terms and conditions listed in Schedule-III to these regulations.

Provided that no broadcaster shall, directly or indirectly, compel any direct to home operator not to make available its direct to home service to any class of subscribers including commercial subscribers.

Provided further that a broadcaster may have a different Reference Interconnect Offer for supply of signals by the direct to home operators ----

- (a) to the following categories of commercial subscribers, namely:-
- (i) hotels with rating of three star and above;
 - (ii) heritage hotels (as described in the guidelines for classification of hotels issued by Department of Tourism, Government of India);
 - (iii) any other hotel, motel, inn, and such other commercial establishment providing board and lodging and having fifty or more rooms; and
- (b) in respect of programmes of such broadcaster, shown on the occasion of a special event for common viewing, at any place registered under the Entertainment Tax Law and to which access is allowed on payment basis for a minimum of fifty persons.

Explanation:

For removal of doubts, it is clarified that the reference interconnect offer containing various terms and conditions including commercial terms, published by a broadcaster for provision of signals to ordinary subscribers shall apply to provision of signals to commercial subscribers not specified in the second proviso.”

(b) in the proviso to regulation 13.2A.2, for the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007)”, the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)” shall be substituted;

(c) in regulation 13.2A.3, -----

(i) for the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007)”, the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)” shall be substituted; and

(ii) for the words “ninety days”, the words “thirty days” shall be substituted;

(d) in regulation 13.2A.4, -----

(i) for the words “ninety days”, the words “thirty days” shall be substituted; and

(ii) for the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007)”, the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)” shall be substituted;

(e) in regulation 13.2A.6, -----

(i) in the second proviso to sub-regulation (1), for the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007)”, the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)” shall be substituted; and

(ii) in sub-regulation (2) and sub-regulation (3), for the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fourth Amendment) Regulation, 2007 (9 of 2007)”, wherever they occur, the words and figures “the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009)” shall be substituted;

(f) in the proviso to regulation 13.2A.11, for the words “the entire bouquet”, the words “any channel or channels or bouquet” shall be substituted.

7. In the principal regulations, after regulation 13.2A.13, the following regulations shall be inserted, namely:-

“13.2B Reference Interconnect Offers for addressable systems other than direct to home service.

13.2B.1 Every broadcaster, providing broadcasting services before the date of commencement of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009) and continues to provide such services after such commencement shall, within thirty days from the date of such commencement, submit its Reference Interconnect Offer specifying, *inter-alia*, the technical and commercial terms and conditions including those listed in Schedule III for interconnection with addressable systems other than -----

(a) cable service in areas notified by the Central Government under sub-section (1) of section 4A of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995);

(b) the direct to home service, -----

to the Authority.

13.2B.2 Every broadcaster, who begins to provide broadcasting services after the date of commencement the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009 (4 of 2009) shall, within thirty days of such commencement or before providing such services, whichever is later, submit to the Authority, its Reference Interconnect Offer specifying therein the technical and commercial terms and conditions referred to in sub-regulation 13.2B.1 and publish the same, before or simultaneously with such intimation, on its website.

13.2B.3 The provisions of regulations 13.2A.1, 13.2A.2, 13.2A.4, 13.2A.5, 13.2A.6, 13.2A.7, 13.2A.8, 13.2A.9, 13.2A.10, 13.2A.11, 13.2A.12 and 13.2A.13, relating to Reference Interconnect Offers for direct to home service, shall apply, mutatis mutandis, to such a Reference Interconnect Offer for interconnection with addressable systems other than cable service in areas notified by the Central Government under sub-section (1) of section 4A of the Cable Television Network (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995) and the direct to home service:

Provided that a broadcaster may have different Reference Interconnect Offers for different types of addressable systems.

13.2B.4 Any distributor of TV channels using an addressable system for distribution of TV channels seeking interconnection with a broadcaster in terms of the Reference Interconnect Offer referred to in regulation 13.2B.1 or 13.2B.2, as the case may be, shall ensure that the addressable system being used for distribution of TV channels satisfies the minimum specifications for addressable systems as specified in Schedule IV to these regulations:

Provided that in cases where a broadcaster is of the opinion that the addressable system being used for distribution of TV channels does not satisfy the minimum specifications for addressable systems as specified in Schedule IV to these regulations, upon being informed of such opinion by the broadcaster, the distributor of TV channels shall get the addressable system audited by M/s. Broadcast Engineering Consultants India Ltd., or any other agency as may be notified by the Authority from time to time for the purpose of such audit and obtain a certificate to the effect that the addressable system being used for distribution of TV channels satisfies the minimum specifications for addressable systems as specified in Schedule IV to these regulations:

Provided further that the finding of M/s. Broadcast Engineering Consultants

India Ltd., or any other agency notified by the Authority in this regard, as the case may be, based on such audit as referred to in the first proviso, about the addressable system being used for distribution of TV channels satisfying or not satisfying the minimum specifications for addressable systems as specified in Schedule IV to these regulations, shall be final.”.

8. In the principal regulations, after Schedule II, the following Schedules shall be inserted, namely:-

“Schedule III

Terms and conditions which should compulsorily form part of Reference Interconnect Offers for interconnection for the direct to home platform and for other addressable platforms

Licence Fee	<p>For each month or part thereof during the Term of the agreement, the DTH operator shall pay to _____ (name of the Broadcaster) the Monthly Licence Fee which shall be the Rate multiplied by the Monthly Average Subscriber Level.</p> <p>The a-la-carte and bouquet “Rate” per Subscriber is set out in Annexure to this RIO. The rates mentioned in the Annexure to this RIO, as referred to above, are exclusive of all taxes and levies.</p> <p>The “Monthly Average Subscriber Level” is equal to the sum of the number of subscribers on the first and last day of the month in question divided by two.</p> <p>For the purpose of calculation of the Monthly License Fee payable to _____ (name of the Broadcaster), “Subscriber” means, for any calendar month, each Set Top Box, which is availing the Channel(s) of _____ (name of the Broadcaster) through the DTH operator.</p> <p><u>Calculation of License Fee:</u></p> <p>I. In case a DTH operator avails one or more Bouquet(s) of _____ (name of the Broadcaster):</p> <p>(a) If the DTH operator is providing the Bouquet(s) as a whole to its DTH subscribers, the Monthly License Fee for such Bouquet(s) shall be equal to the Bouquet rate as set out in the Anenxure multiplied by the number of</p>
-------------	--

monthly average number of subscribers availing the Bouquet(s).

- (b) if the DTH operator does not offer such opted bouquet(s) as a whole to its direct to home subscriber but offers only certain channels comprised in such bouquet or packages the channels comprised in such opted bouquet in a manner resulting in different subscriber base for different channels comprised in such opted bouquet, then the payment to _____ (name of the Broadcaster) for such entire opted bouquet by the DTH operator, shall be calculated on the basis of subscriber base for the channel which has highest subscriber base amongst the channels comprised in the bouquet.

II In case a DTH operator avails one or more or all channels of _____ (name of the Broadcaster) on ala carte rate basis:

- (a) If the DTH operator is providing the channels on ala carte basis to its DTH subscribers, the Monthly License Fee for such ala carte channels shall be equal to the ala carte rate as set out in the Annexure multiplied by the number of monthly average number of subscribers availing the channels on ala carte basis.
- (b) If the DTH operator does not offer such opted ala carte channel(s) as ala carte to its direct to home subscriber but offers the ala carte channel (s) in packages, then the payment to _____ (name of the Broadcaster) for each of the ala carte channels, shall be calculated on the basis of subscriber base of the package in which such opted ala carte channel has been placed.

III In case a DTH operator avails one or more channels on ala carte rate basis and also opts for different Bouquet(s) not comprising of channels opted on ala carte basis of _____ (name of the Broadcaster):

- (a) For bouquet(s), the monthly license fee shall be calculated on the basis of sub clause I above.
- (b) For ala carte channels, the monthly license fee shall be calculated on the basis of sub clause II above.

Payment of the License Fee shall be subject to deduction of any withholding tax/ TDS in accordance with the provisions of

	the Indian Income Tax Act, 1961, as amended from time to time.
Payment Terms	<p>The Monthly Licence Fee shall be paid monthly in arrears within fifteen (15) days of receipt of invoice raised on the basis of report of the DTH operator by _____ (name of the Broadcaster) without any deduction except deduction of withholding tax/TDS as provided in this RIO.</p> <p>Within seven days of end of each month, the DTH operator shall provide opening, closing and average number of subscribers for that month, based on which _____ (name of the Broadcaster) shall raise an invoice on the DTH operator. In case the DTH operator fails to send the report within the said period of seven days, _____ (name of the Broadcaster) shall have the right to raise a provisional invoice and the DTH operator shall be under obligation to pay the license fee on the basis of such provisional invoice in accordance with the terms of this clause. However the provisional invoice shall be for an amount not more than the monthly license fee payable by the DTH operator for the immediately preceding month. On receipt of the report from the DTH operator, the parties would conduct reconciliation between the provisional invoice raised by _____ (name of the Broadcaster) and the report sent by the DTH operator.</p> <p>The DTH operator shall be required to make payments by the Due Date in accordance with the terms hereof, and any failure to do so on the part of the DTH operator shall constitute a material breach hereunder. Late payments shall also attract interest calculated from the date payment was due until the date payment is made in full at a pro rata monthly rate of ____%. The imposition and collection of interest on late payments does not constitute a waiver of the DTH operator's obligation to pay the License Fee by the Due Date, and _____ (name of the Broadcaster) shall retain all of its other rights and remedies under the Agreement.</p> <p>All Licence Fee payments hereunder are exclusive of all applicable indirect taxes including all and any service taxes, VAT, works contract taxes, customs duties, excise duties, entertainment taxes and other such taxes. All such taxes shall be at DTH operator's cost and will be charged at the prevailing rates by _____ (name of the Broadcaster) to the DTH operator.</p>

	<p>If payment of the Licence Fee is subject to deduction of any withholding tax/TDS in accordance with the provisions of the Indian Income Tax Act 1961, as amended, the DTH operator shall provide tax withholding certificates to _____ (name of the Broadcaster) within such period as has been specified in the Income Tax Act/ Rules/ Notifications/ Circulars issued thereunder.</p>
Delivery and Security	<p>All _____ (name of the Broadcaster) Channels must be delivered by DTH operator to subscribers in a securely encrypted manner and without any alteration.</p> <p>The uplink specifications, satellite capacity and infrastructure allocated by DTH operator in respect of the broadcast signal of the _____'s (name of the Broadcaster) Channels by DTH operator to its subscribers shall be no worse than that of the broadcast signal of any other channel within the same genre on its DTH platform.</p>
Anti-Piracy	<p>In order to prevent theft, piracy, unauthorized retransmissions, redistribution or exhibition, copying or duplication of any Channel, in whole or in part, (hereinafter collectively referred to as "Piracy"), the DTH operator shall, prior to the commencement of the Term of the agreement and at all times during such Term, employ, maintain, and enforce fully effective conditional access delivery and content protection and security systems, and related physical security and operational procedures (hereinafter collectively referred to as the "Security Systems") as may be specified (security specifications), in a non-discriminatory manner in writing, from time to time, by the _____ (name of the Broadcaster).</p> <p>To ensure the DTH operator's ongoing compliance with the security requirements set out in the Agreement, _____ (name of the Broadcaster) may require technical audits ("Technical Audit(s)") conducted by an independent security technology auditor ("Technical Auditor"), approved by _____ (name of the Broadcaster) in writing no more than twice per year during the Term, at _____ (name of the Broadcaster)'s cost and expense. If the results of any Technical Audit are not found to be satisfactory by either the DTH operator or _____ (name of the Broadcaster), then _____ (name of the Broadcaster) shall work with the DTH Operator in resolving this issue in the next fourteen (14) business days. If a solution is not reached at by then, _____ (name of Broadcaster) may, in its sole discretion, suspend the DTH operator's right to distribute the Channels or take other actions as provided under the Agreement, until such systems, procedures and security measures have been corrected to _____ (name of the</p>

Broadcaster)'s satisfaction. DTH operator shall bear the cost and expense of any subsequent Technical Audit to verify that the systems, procedures and security measures have been corrected by the DTH operator to _____ (name of the Broadcaster)'s satisfaction.

DTH operator shall deploy finger printing mechanisms to detect any piracy, violation of copyright and unauthorized viewing of the Channels, distributed / transmitted through its Platform at least every 10 minutes on 24 x 7 x 365(6) basis.

DTH operator shall not authorize, cause or suffer any portion of any of the Channels to be recorded, duplicated, cablecast, exhibited or otherwise used for any purpose other than for distribution by DTH operator at the time the Channels are made available. If DTH operator becomes aware that any unauthorized third party is recording, duplicating, cablecasting, exhibiting or otherwise using any or all of the Channels for any other purpose, DTH operator shall within ten minutes of so becoming aware of such recording, duplicating, cablecasting, exhibiting or otherwise using any or all of the Channels for any other purpose, notify _____ (name of the Broadcaster) and the DTH operator shall also switch off the concerned Set Top Box to prevent such unauthorized use. However, use of a Set Top Box with Personal Video Recorder/ Digital Video Recorder facility which has been supplied by the DTH operator shall not be treated as unauthorized use, as long as such Set Top Box is used in accordance with the terms and conditions of the subscription agreement between the DTH operator and the subscriber.

If so instructed by Information (as defined below) by _____ (name of the Broadcaster), the DTH operator shall shut off or de-authorize the transmission to any unauthorized subscriber/ subscriber indulging in piracy, within ten minutes from the time it receives such instruction from _____ (name of the Broadcaster). Any communication under this clause shall be considered as valid Information only if (i) the information is sent through e mail in a format as mutually agreed by the parties and (ii) the information is sent by a person(s) who is designated to send such information. However the "information" may even be provided by _____ (name of the Broadcaster) representatives through other means of communications such as telephonic message, fax etc and the said "information" shall later be confirmed by _____ (name of the Broadcaster) through e mail and the DTH operator shall be under obligation to act upon such information.

Reports	<p>DTH operator will maintain at its own expense a subscriber management system ("SMS") which should be fully integrated with the CAS (Conditional Access System).</p> <p>DTH operator shall provide to _____ (name of the Broadcaster) complete and accurate opening and closing subscriber monthly reports for the _____ (name of the Broadcaster) Channels and the tier and/or package containing the _____ (name of the Broadcaster) Channels within seven (7) days from the end of each month in the format provided by _____ (name of the Broadcaster).</p> <p>Such reports shall specify all information required to calculate the Monthly Average Subscriber Level (including but not limited to the number of Subscribers for each _____ (name of the Broadcaster) Channel and each package in which a _____ (name of the Broadcaster) Channel is included) and the Licence Fees payable to _____ (name of the Broadcaster) and shall be signed and attested by an officer of the DTH operator of a rank not less than Head of Department/Chief Financial Officer who shall certify that all information in the Report is true and correct.</p>
Audit	<p>_____ (name of the Broadcaster)'s representatives shall have the right, not more than twice in a calendar year, to review and / or audit the subscriber management system, conditional access system, other related systems and records of Subscriber Management System of the DTH operator relating to the Channel(s) provided by the broadcaster for the purpose of verifying the amounts properly payable to _____ (name of the Broadcaster) under the Agreement, the information contained in Subscriber Reports and full compliance with the terms and conditions of the Agreement. If such review and or audit reveals that additional fees are payable to _____ (name of the Broadcaster), the DTH operator shall immediately pay such fees, as increased by the Late Payment Interest Rate. If any fees due for any period exceed the fees reported by the DTH operator to be due for such period by two (2) percent or more, DTH operator shall pay all of _____ (name of the Broadcaster)'s costs incurred in connection with such review and / or audit, and take any necessary actions to avoid such errors in the future.</p> <p>The DTH operator shall remain the sole owner and holder of all customer databases compiled by the DTH operator under the Agreement.</p> <p>DTH operator will maintain at its own expense a subscriber management system ("SMS") capable of, at a minimum:</p> <p>(i) maintaining a computerised customer database capable of recording adequate details of each Subscriber, including name, address, chosen method of payment and billing;</p>

	<p>(ii) administering subscriptions of Subscribers by producing and distributing contracts for new Subscribers and setting up and maintaining an infrastructure whereby Subscriber contracts are collected and recorded in the SMS database for ongoing administration;</p> <p>(iii) handling all ongoing administrative functions in relation to Subscribers, including, without limitation, billing and collection of subscription payments, credit control, sales enquiries and handling of complaints;</p> <p>(iv) administering payments of any commission fees from time to time payable to the DTH operator's authorised agents for the sale to Subscribers of programming packages;</p> <p>(v) obtaining and distributing receivers and smartcards, if applicable, to Subscribers, and issue replacement smartcards from time to time in its discretion; and</p> <p>(vi) enable new Subscribers via the SMS over-the-air addressing system and disable defaulting Subscribers from time to time in its discretion.</p>
Term	<p>AS mutually agreed between _____ (name of the Broadcaster) and the DTH operator subject to a minimum of One (1) Year from the date of signing of the Agreement unless terminated earlier in accordance with the Agreement.</p> <p>The Term of the Agreement may be extended on terms and conditions to be mutually agreed and recorded in writing between the parties.</p>
Termination	<p>Either Party has a right to terminate this Agreement by a written notice, subject to applicable Law, to the other in the event of:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. material breach of this Agreement by the other Party which has not been cured within thirty (30) days of being required in writing to do so; 2. the bankruptcy, insolvency or appointment of receiver over the assets of the other Party; 3. The DTH licence or any other material licence necessary for DTH operator to operate its DTH service being revoked at anytime other than due to the fault of DTH operator. <p>_____ (name of the Broadcaster) shall have the right to terminate this Agreement by a written notice to DTH operator if (i) DTH operator breaches any of the Anti Piracy Requirements and fails to cure such breach within ten (10) days of being required in writing to do so; or</p> <p>(ii) _____ (name of the Broadcaster) discontinues the _____ (name of the Broadcaster) Channels with respect to all distributors in the Territory and provides DTH operator with at least ninety (90) days prior written notice.</p>

(B) BOUQUET RATES**BOUQUET - 1**

Channels	Rate to DTH operator (Rs)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

BOUQUET 2

Channels	Rate to DTH operator (Rs)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

BOUQUET 3

Channels	Rate to DTH operator (Rs)
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

Schedule IV

Specifications for Set-Top-Boxes (STBs), Conditional Access System (CAS) & Subscribers Management System (SMS) for implementation of Digital Addressable Systems

(A) STB Requirements:

1. All the STBs should have embedded Conditional Access.
2. The STB should be capable of decrypting the Conditional Access inserted by the Headend.
3. The STB should be capable of doing Finger printing. The STB should support both Entitlement Control Message (ECM) & Entitlement Management Message (EMM) based fingerprinting.
4. The STB should be individually addressable from the Headend.
5. The STB should be able to take the messaging from the Headend.
6. The messaging character length should be minimal 120 characters.
7. There should be provision for the global messaging, group messaging and the individual STB messaging.
8. The STB should have forced messaging capability.
9. The STB must be BIS compliant.
10. There should be a system in place to secure content between decryption & decompression within the STB.
11. The STBs should be addressable over the air to facilitate Over The Air (OTA) software upgrade.

(B) Fingerprinting Requirements:

1. The finger printing should not be removable by pressing any key on the remote.
2. The Finger printing should be on the top most layer of the video.
3. The Finger printing should be such that it can identify the unique STB number or the unique Viewing Card (VC) number.
4. The Finger printing should appear on all the screens of the STB, such as Menu, EPG etc.
5. The location of the Finger printing should be changeable from the Headend and should be random on the viewing device.
6. The Finger printing should be able to give the numbers of characters as to identify the unique STB and/ or the VC.
7. The Finger printing should be possible on global as well as on the individual STB basis.
8. The Overt finger printing and On screen display (OSD) messages of the respective broadcasters should be displayed by the MSO/LCO without any alteration with regard to the time, location, duration and frequency.
9. No common interface Customer Premises Equipment (CPE) to be used.
10. The STB should have a provision that OSD is never disabled.

(C) CAS & SMS Requirements:

1. The current version of the conditional access system should not have any history of the hacking.
2. The fingerprinting should not get invalidated by use of any device or software.
3. The STB & VC should be paired from head-end to ensure security.
4. The SMS and CA should be integrated for activation and deactivation process from SMS to be simultaneously done through both the systems. Further, the CA system should be independently capable of generating log of all activations and deactivations.
5. The CA company should be known to have capability of upgrading the CA in case of a known incidence of the hacking.
6. The SMS & CAS should be capable of individually addressing subscribers, on a channel by channel and STB by STB basis.
7. The SMS should be computerized and capable to record the vital information and data concerning the subscribers such as:
 - a. Unique Customer Id
 - b. Subscription Contract no
 - c. Name of the subscriber
 - d. Billing Address
 - e. Installation Address
 - f. Landline no
 - g. Mobile No
 - h. Email id
 - i. Service /Package subscribed to
 - j. Unique STB No
 - k. Unique VC No
8. The SMS should be able to undertake the:
 - a. Viewing and printing historical data in terms of the activations, deactivations etc
 - b. Location of each and every set top box/VC unit
 - c. The SMS should be capable of giving the reporting at any desired time about:
 - i. The total no subscribers authorized
 - ii. The total no of subscribers on the network
 - iii. The total no of subscribers subscribing to a particular service at any particular date.
 - iv. The details of channels opted by subscriber on a-la carte basis.
 - v. The package wise details of the channels in the package.
 - vi. The package wise subscriber numbers.
 - vii. The ageing of the subscriber on the particular channel or package
 - viii. The history of all the above mentioned data for the period of the last 2 years
9. The SMS and CAS should be able to handle at least one million concurrent subscribers on the system.

10. Both CA & SMS systems should be of reputed organization and should have been currently in use by other pay television services that have an aggregate of at least one million subscribers in the global pay TV market.
11. The CAS system provider should be able to provide monthly log of the activations on a particular channel or on the particular package.
12. The SMS should be able to generate itemized billing such as content cost, rental of the equipments, taxes etc.
13. The CA & SMS system suppliers should have the technical capability in India to be able to maintain the system on 24x7 basis throughout the year.
14. CAS & SMS should have provision to tag and blacklist VC numbers and STB numbers that have been involved in piracy in the past to ensure that the VC or the STB can not be re-deployed. ”.

N. PARAMESWARAN, Principal Advisor (B&CS)

[ADVT III/4/142/2008/Extty.]

Note 1.—The principal regulations were published vide notification no. 8-26/2004-B&CS dated 10th December, 2004 and subsequently amended vide notifications no.3-57/2005-B&CS dated 3rd March, 2005, no.11-13/2006-B&CS dated 24th August, 2006, no. 6-4/2006-B&CS dated 4th September, 2006 and no. 4-54/2007-B&CS dated 3rd September, 2007.

Note 2.—The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection (Fifth Amendment) Regulation, 2009.

Annex

EXPLANATORY MEMORANDUM

Background

1. The Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004, was issued on 10th December, 2004 to provide for a regulatory framework for interconnection in respect of broadcasting and cable services. These regulations were issued to enable the distributors of TV channels to get non discriminatory access to content of all broadcasters and to mandate issue of a public notice by a broadcaster or MSO, as the case may be, before disconnection of signals so as to enable the consumers to protect their interests.
2. These Regulations have been amended four times since their issue. The amendment regulations were issued on 3rd March, 2005, 24th August, 2006, 4th September, 2006 and 3rd September, 2007 for amplification and modification of the existing provisions and to cover some new issues that had not been covered in the

Regulations till then. Such amendments were necessitated by changes over time in the broadcasting and cable services sector on account of notification of CAS, growth of DTH and other addressable systems and experience gained in implementation of the interconnection regulation. Recently, a need has again been felt to consider amendments to these regulations on certain issues relating to addressable and non-addressable platforms. Accordingly, a consultation process was initiated as mentioned ahead.

Consultation Process

2. Sub-clause (ii), (iii) and (iv) of clause (b) of sub-section (1) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (hereinafter referred to as the TRAI Act, 1997), provides for the Authority to “(ii)...fix the terms and conditions of inter-connectivity between the service providers;”, “(iii) ensure technical compatibility and effective inter-connection between different service providers;” and “(iv) regulate arrangement amongst service providers of sharing their revenue derived from providing telecommunication services;”. Sub-section (4) of Section 11 of the TRAI Act, 1997 requires the Authority to ensure transparency while exercising its powers and discharging its functions. Accordingly, the Authority decided to go in for a consultation process before amending the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004.

3. The process of consultation was initiated by circulating a consultation paper on Interconnection issues relating to Broadcasting & Cable on 15th December, 2008 inviting inputs from the stakeholders. Responses were received from 29 stakeholders/representatives. An open house discussion was also held on the 6th February, 2009 in Kolkata with representatives of stakeholders to further deliberate on various issues raised in the consultation paper. The Authority had released the draft amendment regulation for amending the Interconnection Regulations on its website on 26th February, 2009 for seeking comments of the stakeholders. The comments were invited till 7th March, 2009. Responses were received from 9 stakeholders. These comments have been taken into consideration while finalizing the regulations.

Issues for Consultation

4. The issues which were raised for consultation in the consultation paper are reproduced below.

A. Interconnection for Addressable Platforms

A.1 Whether the Interconnection Regulation should make it mandatory for the broadcasters to publish Reference Interconnect Offers (RIOs) for all addressable systems, and whether such RIOs should be same for all addressable systems or

whether a broadcaster should be permitted to offer different RIOs for different platforms?

- A.2 Is there any other methodology which will ensure availability of content to all addressable platforms on non-discriminatory basis?
- A.3 What should be the minimum specifications/ conditions that any TV channel distribution system must satisfy to be able to get signals on terms at par with other addressable platforms? Are the specifications indicated in the Annexure to the Consultation Paper adequate in this regard?
- A.4 What should be the methodology to ensure and verify that any distribution network seeking to get signals on terms at par with other addressable platforms satisfies the minimum specified conditions for addressable systems?
- A.5 What should be the treatment of hybrid cable networks in non-CAS areas which provide both types of service, i.e., analogue (without encryption) and digital (with encryption) services?
- A.6 Whether there is a need to define “Commercial Subscribers”, and what should be that definition?
- A.7 Whether the Broadcasters may be mandated to publish RIOs for all addressable platforms for Commercial Subscribers as distinct from broadcasters’ RIOs for non-Commercial Subscribers?
- A.8 Whether the regulation should mandate publishing of Reference Interconnect Agreements (RIAs) for addressable systems instead of Reference Interconnect Offers (RIOs)?
- A.9 Whether the time period of 45 days prescribed for signing of Interconnection Agreements should be reduced if RIOs are replaced by RIAs as suggested above?
- A.10 Whether the regulation should specifically prohibit the broadcasters from imposing any kind of restrictions on packaging of channels on an addressable platform?
- A.11 Whether the regulation should specifically prohibit the broadcasters from imposing any kind of restrictions on pricing of channels on an addressable platform?
- B. Interconnection for non-addressable platforms**
- B.1 Whether the terms & conditions and details to be specifically included in the RIO for non-addressable systems should be specified by the Regulation as has been done for DTH?

B.2 What terms & conditions and details should be specified for inclusion in the RIO for non-addressable systems?

C. General Interconnection Issues

C.1 Whether it should be made mandatory that before a service provider becomes eligible to enjoy the benefits/ protections accorded under interconnect regulations, he must first establish that he fulfills all the requirements under quality of service regulations as applicable?

C.2 Whether applicability of clause 3.2 of the Interconnect Regulation should be restricted so that a distributor of TV channels is barred from seeking signals in terms of clause 3.2 of the Interconnect Regulation from a broadcaster for those channels in respect of which carriage fee is being demanded by the distributor of TV channels from the broadcaster?

C.3 Whether there is a need to regulate certain features of carriage fee, such as stability, transparency, predictability and periodicity, as well as the relationship between TAM/TRP ratings and carriage fee.

C.4 If so, then what should the manner of such regulation be.

C.5 Whether the standard interconnect agreement between broadcasters and MSOs should be amended to enable the MSOs, which have been duly approved by the Government for providing services in CAS areas, to utilize the infrastructure of a HITS operator for carriage of signals to the MSO's affiliate cable operators in CAS areas?

C.6 Whether the standard interconnect agreement between broadcasters and HITS operators need to be prescribed by the Authority, and whether these should be broadly the same as prescribed between broadcasters and MSOs in CAS notified areas?

C.7 What further regulatory measures need to be taken to ensure that DTH operators are able to provide six month protection for subscribers as provided by Sub clause (1) of Clause 9 of the Direct to Home Broadcasting Services (Standards of Quality of Service and Redressal of Grievances) Regulations, 2007?

C.8 Towards this objective, should it be made mandatory for broadcasters to continue to provide signals to DTH operators for a period of six months after the date of expiry of interconnection agreement to enable the DTH operators to discharge their obligation?

C.9 Is there any other regulatory measure which will achieve the same objective?

D. Registration of Interconnection Agreements

- D.1 Whether it should be made mandatory for all interconnect agreements to be reduced to writing?
- D.2 Whether it should be made mandatory for the Broadcasters/ MSOs to provide signals to any distributor of TV channels only after duly executing a written interconnection agreement?
- D.3 Whether no regulatory protection should be made available to distributors of TV channels who have not executed Interconnect Agreements in writing?
- D.4 How can it be ensured that a copy of signed interconnection agreement is given to the distributor of TV channels?
- D.5 Whether it should be the responsibility of the Broadcaster to hand over a copy of signed Interconnect Agreement to MSO or LCO as the case may be, and obtain an acknowledgement in this regard? Whether similar responsibility should also be cast on MSOs when they are executing interconnection agreements with their affiliate LCOs?

Analysis of the responses received during the consultation process**RIO for all addressable systems**

5. Most of the broadcasters were in favour of having RIOs for all addressable systems. However, a few broadcasters were opposed to the idea. All the distributors of TV channels wanted the broadcasters to publish RIOs for all addressable systems. Individuals and consumer groups also favoured the concept of RIOs for all addressable systems. However, on the issue of having same RIO for all addressable platforms, there was no unanimity amongst the broadcasters. The distributors of TV channels were also divided in their views on the subject.

Minimum specifications for addressable systems

6. Most of the Broadcasters were of the view that the specifications for addressable systems as given in the annexure to the Consultation paper were insufficient. The distributors of TV channels were divided in their views. While the consumer groups felt that the specifications were sufficient, the individuals termed the specifications for addressable systems as given in the annexure as inadequate.

Commercial Subscribers

7. Most of the broadcasters suggested that there was a need for defining "commercial subscribers". All the distributors of TV channels, with the exception of two DTH operators, also agreed with this view. The two DTH operators, who opposed the need for defining "commercial subscribers", have suggested that no distinction should be made between commercial and residential subscribers. It has been asserted by these DTH

operators that in case of an addressable platform, each and every subscriber is accounted for and therefore there should not be any distinction between residential and commercial subscribers. Same rates and terms and conditions should apply for supply of signals by addressable platforms to all types of subscribers including commercial subscribers. The consumer groups and individuals have also favoured defining "commercial subscribers". As regards the issue of mandating broadcasters to publish RIOs for all addressable platforms for commercial subscribers, most of the broadcasters agreed to such an amendment. All the distributors of TV channels, with the exception of two DTH operators, also wanted the broadcasters to be mandated to publish RIOs for all addressable platforms for commercial subscribers. The two DTH operators, who opposed the need for such RIOs for commercial operators, have suggested that no distinction should be made between commercial and residential subscribers.

Reference Interconnect Agreements for all addressable systems

8. The proposal has been opposed by most of the broadcasters. On the other hand, most of the distributors of TV channels have supported the proposal. The consumer groups and individuals have also supported the proposal.

Restrictions on packaging/ pricing of channels

9. All the broadcasters have opposed any kind of prohibition on broadcasters from imposing packaging restrictions on addressable platforms. All the distributors of TV channels want such a prohibition to be mandated. The consumer groups and individual stakeholders have also favoured such a prohibition. Similar comments have been received regarding prohibition on broadcasters from imposing pricing restrictions on addressable platforms. However, one broadcasting company has agreed with the concept of restricting broadcasters from imposing pricing restrictions on addressable platforms. It has been stated by this broadcasting company that there is severe competition on the ground amongst platforms hence market forces should determine the pricing of channels by the platforms and the broadcasters should not be allowed to impose any restrictions on pricing of channels.

Interconnection for Non addressable platforms

10. The Eighth Amendment to the Non-CAS Tariff Order has been set aside by the Hon'ble TDSAT by its judgment dated 15th January, 2009 in Appeal No. 9(C) of 2006 and Appeal Nos. 10(C), 11(C), 12(C), 13(C) and 15(C) of 2007. Accordingly, the Authority has not deemed it appropriate at present to examine the issues relating to

interconnection for non-addressable platform because the objective of the proposed amendment relating to interconnection for non-addressable platforms was to harmonize the provisions of interconnection regulations with those of the tariff order.

Compliance with Quality of Service Regulations

11. Most of the stakeholders have favoured the concept that before a service provider becomes eligible to enjoy the benefits/ protections accorded under interconnect regulations, he must first establish that he fulfills all the requirements under quality of service regulations as applicable. However, this has been opposed by two of the DTH operators on the ground that such a move will deny the benefit of smoother inter connection and distribution of content, and could be a retrograde step and that linking the two issues would only create confusion and would give an excuse to Broadcasters for not providing signals to Service Provider on a non-discriminatory basis.

Carriage Fee – restricting the applicability of clause 3.2 of the Interconnect Regulation

12. All the broadcasters have demanded that the “must provide” provision should be restricted for those channels in respect of which carriage fee is being demanded by the distributor of TV channels. On the other hand, all the distributors of TV channels have opposed such a restriction. The consumer groups have agreed with the view of the broadcasters and the individual stakeholders are divided on the issue.

Carriage Fee – need for regulation

13. The distributors of TV channels have opposed any kind of regulation of carriage fee. It has been asserted by them that the issue is very complex and intricate and that there cannot be one universal rule for governing the carriage fee. It has been pointed out that the addressable platforms suffer huge operational losses due to mismatch between infrastructure cost and the meager subscription revenues. It has been highlighted that the advertisement revenue of a Broadcaster is incapable of being regulated, similarly carriage fee needs to be left to market forces to decide because the two are intimately linked. On the other hand the broadcasters have demanded some regulation of carriage fee. One broadcaster has suggested that the Regulator must achieve this purpose through a separate consultation process and through a process of constitution of a core consultative committee comprising all stakeholders to come up with a workable balanced mechanism

Standard Interconnect Agreements for CAS areas – use of HITS operator infrastructure

14. All the distributors of TV channels have demanded amendment in standard interconnect agreements for CAS areas to enable MSOs to utilize the infrastructure of HITS operators for carrying signals. Similar views have been expressed by consumer groups. The broadcasters are divided on this issue. On the issue of need for prescribing standard interconnect agreements between Broadcasters and HITS operators, all the segments of stakeholders, namely broadcasters, distributors of TV channels and consumers are divided.

Tariff protection for DTH subscribers

15. The broadcasters are opposed to any kind of compulsion on broadcasters to continue to provide signals to DTH operators for a period of six months after the date of expiry of interconnection agreement to enable the DTH operators to discharge their obligation. The DTH operators want such a provision to be introduced. The MSOs are divided on the issue and the consumer groups agree with the broadcasters.

Mandating Written Interconnection Agreements

16. Almost all the stakeholders suggested that it should be mandatory for all interconnection agreements to be in writing. One broadcaster opposed the proposal on the ground that there should be no regulation in this regard. One DTH operator has commented that written interconnection agreements is not a requirement of law of the Country (As per the Contract Act) and therefore such requirement would be contrary to the established legal principles. Another DTH operator has opined that manner of entering into Interconnect Agreement is an operational matter and may be left to market forces to decide.

17. Most of the stakeholders are in favour of making it mandatory for the Broadcasters/ MSOs to provide signals only after duly executing a written interconnection agreement. However, a view has also been expressed that on finalization of terms and conditions, signals should be provided with an undertaking to execute an agreement within a stipulated time. One stakeholder has also pointed out that sometimes

signals are provided in compliance with the directions of courts of law without any formal agreement.

18. Most of the stakeholders have favoured withdrawal of regulatory protection to distributors of TV channels who have not executed interconnect agreements in writing. Similarly, on the issue of fixing responsibility for handing over copies of signed agreements to MSO/ LCO, most stakeholders want the Broadcaster/ MSO to be held responsible.

Analysis of the responses received during the second stage consultation process

19. One MSO and one DTH operator suggested that the definition of IPTV should be incorporated in the Interconnection Regulations as the Ministry of Information & Broadcasting has already issued the guidelines for provisioning of IPTV services on 8th September, 2008.

20. On the issue of restricting the applicability of Clause 3.2 of Interconnect Regulations in cases where carriage fee is also being demanded, two MSOs opposed the proposed amendment. The broadcasters have agreed with the proposed amendment. One DTH operator and one MSO have suggested that such a restriction should not prevent the distributors from charging placement fee.

21. Proposed amendment mandating written agreements was welcomed by one broadcaster, whereas another broadcaster opposed the proposal saying that such a stipulation imposed a commercial cost on the broadcasters. One DTH operator referred to the Contract Act and asserted that written agreements are not mandatory as per the Contract Act. It was pointed out by one DTH operator and one MSO that sometimes signals are provided in compliance of Court orders and the proposed amendment should take into account such cases also.

22. The proposed amendment requiring broadcasters and MSOs to hand over a copy of signed interconnect agreement to MSOs/ cable operators has been opposed by one broadcaster. Other stakeholders have welcomed the move. It has been suggested by two stakeholders that a time limit should be specified for handing over copies of signed agreements by the broadcasters, MSOs or HTS operators, as the case may be.

23. Two stakeholders have suggested amendments in Regulation 13.2A to specify the time limits for issue of revised RIOs by the Broadcasters for DTH operators. A time limit of seven days has been suggested.

24. The proposed amendments for enabling the DTH operators to supply signals to commercial subscribers have been welcomed by all the stakeholders except for one broadcaster who has opposed the amendment and asserted that the commercial subscribers have sufficient bargaining power to protect their interests. One stakeholder has welcomed the proposal to enable the DTH operators to supply signals to commercial subscribers and at the same time opposed any distinction between residential and commercial subscribers in the matter of RIO.

25. The proposed amendment regarding different RIO for commercial subscribers has been opposed by a broadcaster. The broadcaster has commented that if such a regulation has to be made, then different RIOs for different commercial subscribers should be permitted. Some other stakeholders have commented that permitting different RIOs for different addressable systems is a welcome step.

26. Two stakeholders have suggested amendments in Regulation 13.2B.1 to specify the time limits for issue of revised RIOs by the Broadcasters for addressable systems. A time limit of fifteen days has been suggested.

Rationale for making amendment to the Telecommunication (Broadcasting and Cable Services) Interconnection Regulation, 2004

27. The Authority noted that with the advancement of technology the marketshare of addressable systems for distribution of TV channels is set to rise in coming years. Apart from DTH, the HITS and IPTV platforms are already present in the pay TV market. Digitalization of cable TV networks and introduction of voluntary CAS has also started in different pockets in the country. Therefore, the Authority felt that the interconnection regulations should facilitate interconnection agreements for addressable systems. Further, most of the stakeholders are in favour of having RIOs for all addressable platforms. Accordingly, the Authority has mandated publishing of RIOs for all addressable platforms by the broadcasters (other than cable service in CAS notified

areas). At the same time, the Authority has permitted the broadcasters to have different RIOs for different addressable systems. This flexibility has been given to the broadcasters to customize their RIOs depending upon different characteristics of different addressable systems. The definition of Internet Protocol Television Service (IPTV) has been inserted in the Regulations as the Ministry of Information & Broadcasting has already issued the guidelines for provisioning of IPTV services on 8 September, 2008 and many service providers have already rolled out their IPTV services.

28. The Authority also recognized the fact that certain minimum specifications of an addressable system need to be specified upfront so as to minimize disputes in this regard between broadcasters and distributors of TV channels. The Authority has decided to adopt the same minimum specifications for addressable systems (with minor modifications) which was earlier recommended by the expert group consisting of members drawn from TRAI, Ministry of Information & broadcasting, Prasar Bharti, Broadcasters, MSOs, DTH operators, Cable Operator Distributor associations and consumer organizations constituted by the Authority to deliberate on the issues relating to Digitalization and Introduction of Voluntary CAS. These specifications were annexed as Annexure C to the report submitted by the expert group. Moreover, a mechanism has also been put in place for audit of such addressable system where the broadcaster is of the opinion that the addressable system deployed by a distributor of TV channels does not meet the minimum specifications.

29. The Authority has decided to not to lay down specific regulations in respect of hybrid cable networks in non-CAS areas which provide both types of service, i.e., analogue (without encryption) and digital (with encryption) services, as the interconnection regulations take care of addressable as well as non-addressable systems. Finer details can be worked out by the parties through commercial negotiations.

30. The Authority has also noted that the RIOs published by many broadcasters prohibit DTH operators from making available their services to subscribers other than residential subscribers. The Authority is of the view that such a stipulation prevents the DTH operators from supplying services to a large number of subscribers who may be interested in availing their services. At the same time, the interests of the broadcasters also need to be protected. Accordingly, the Authority has prohibited the broadcasters

from, directly or indirectly, compelling any DTH operator not to make available its direct to home service to any class of subscribers including commercial subscribers. At the same time, the broadcasters have been permitted to have a different Reference Interconnect Offer for supply of signals by the DTH operators to specified commercial subscribers as listed in item (ii) of sub-clause (f) of clause 2 of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Second) Tariff Order 2004 as amended from time to time. These provisions are also applicable for RIOs for other addressable platforms.

31. The Authority has decided against mandating Reference Interconnect Agreements (RIAs) for addressable systems. Instead it was felt that the important terms and conditions of RIOs must be specified by the Authority so as to ensure that there are no provisions in the RIOs which are contrary to the objectives sought to be achieved by the Regulations. The Authority felt that RIAs need not be mandated in place of RIOs as the important terms and conditions have already been specified by the Authority.

32. The Authority has amended regulation 13.2A.11 to ensure that the DTH operators and other addressable platforms have complete flexibility regarding packaging of channels taken from any broadcaster. As regards pricing restrictions on channels on addressable platforms, the Authority is of the view that this is a commercial issue to be settled mutually by the broadcasters and distributors of TV channels.

33. The issue of whether fulfillment of all the requirements under quality of service regulations as applicable should be made a precondition for a service provider to become eligible to enjoy the benefits/ protections accorded under interconnect regulations has been analyzed in detail by the Authority. The Authority decided against introducing such a provision because it was felt that such a provision could open floodgates of litigation.

34. The Authority has decided against regulation of carriage fee at this stage for the following reasons:-

- a. Carriage Fee is a market driven phenomenon and the levels of carriage Fee are determined by play of market forces. Carriage fee is a direct result of demand-supply mismatch due to capacity constraints of distribution platforms.
- b. Payment of Carriage/ Placement/ Technical Fee by a broadcaster is intimately linked with the perceived benefit that the broadcaster would enjoy by way of increased

advertising revenue. This linkage is manifested by higher levels of Carriage Fee in TAM cities (cities where the rating agencies have installed their metering devices in sample households). Therefore, regulation of Carriage Fee cannot be done in isolation without regulating the advertising revenue.

- c. Payment of Carriage Fee ultimately gets recovered from the advertisers on TV channels by way of higher advertisement charges. However, no objections have been made by any advertiser in this regard so far.
- d. Carriage Fee has emerged in the market primarily as a result of inadequate digitalization in the Broadcasting & Cable TV market in the country. A view has also been expressed by some distributors of TV channels that Carriage Fee is genuinely required to promote digitalization. Any attempt to regulate it by way of ceiling or specifying a charge on carriage may slow down deployment of digital networks.
- e. The payment of Carriage Fee is often done in cash or kind (equipment for head-end, foreign tours, gifts etc.). Moreover many of the distributors of TV channels receiving Carriage Fee are small operators and their accounts are not subject to statutory audit. Therefore any regulation of Carriage Fee is bound to be a very porous regulation. Further, enforcement problems are anticipated in Carriage Fee regulation which may lead to other distortions in the market.
- f. If some kind of ceiling is laid down for carriage fee, then there is a possibility that more channels may be willing to pay the maximum permissible Carriage Fee than the number of available channel slots. Selection of which channels to carry in such a situation would again result in covert deals.
- g. There are some distributors of TV channels having other businesses (such as newspapers, radio stations, amusement parks etc.) also. If such distributors of TV channels start collecting carriage fee disguised as payments for other goods or services sold by other companies within the group, then it will be practically impossible to regulate carriage fee.
- h. Carriage Fee is also linked with popularity of a channel, which in turn is determined by the market. In such a scenario, laying down a carriage fee regime through regulation for channels of varying popularity will be extremely difficult.
- i. There is no suitable mechanism for enforcement of any regulation on carriage Fee.

35. However, the Authority has amended regulation 3.2 to restrict its applicability in respect of those channels in respect of which any fee is being demanded by the

distributor of TV channels from a broadcaster for carriage of the channels on its distribution platform. This has been done to ensure that the broadcasters are not forced to supply their channel in terms of regulation 3.2 and at the same time forced to pay carriage fee for the same channel. This amendment has been made to prevent a distributor of TV channels from misusing the regulation 3.2. However, this amendment does not prevent the distributor of TV channels from charging a fee for placement of the channel of a broadcaster vis-à-vis channels of other broadcasters on its distribution platform, in case the broadcaster wants the channel to be placed at a particular frequency spot.

36. The “placement fee” is paid by the broadcasters to the distributors of TV channels for placing their channel(s) at the desired frequency/tier/package for maximizing viewership and revenue of their channel(s). The placement fee is different from “carriage fee” and the said aspect has been explicitly recognized by the Authority by defining these two terms separately in the definition clause. The amendment seeks to address the issue of carriage fee only and not the placement fee, which is governed by the market forces and mutual negotiations between the broadcaster(s) and distributor(s) of TV channel.

37. The Ministry of Information & Broadcasting has not issued licensing policy for HITS platforms as yet. In such a scenario, the Authority did not deem it fit to come out with any regulations relating to HITS operators at present. Accordingly, the issues relating to HITS have not been addressed in the amendment regulation.

38. The Authority felt that the objective of providing six month tariff protection for DTH subscribers can be achieved by the DTH operators by appropriate interconnection agreements with the Broadcasters. Further, the DTH operators also have the option of stopping enrolment of new subscribers for a package from which a channel is to be dropped in coming six months. Accordingly, the Authority has decided not to introduce any regulatory measures at this stage for helping the DTH operators in providing six month tariff protection for subscribers as provided by Sub clause (1) of Clause 9 of the Direct to Home Broadcasting Services (Standards of Quality of Service and Redressal of Grievances) Regulations, 2007

39. The Authority is of the opinion that absence of written interconnection agreements leads to a large number of disputes. Further, it is not possible to record oral agreements in the Register of Interconnection Agreements. In view to bring transparency in the sector the Authority has mandated that no broadcaster of pay channels or distributor of TV channels, such as multi system operator or headend in the sky operator, shall make available TV channel signals to any distributor of TV channels without entering into a written interconnection agreement. Further, the responsibility to hand over a copy of signed interconnection agreement to the distributor of TV channels and obtain an acknowledgement in this regard has been placed on the broadcasters of pay channels. Similar responsibility has been cast upon the multi system operators to hand over a copy of signed interconnection agreement to the cable operators and obtain an acknowledgement in this regard.

40. The Authority has not specified the minimum necessary details to be included in any interconnection agreement. Thus, a term sheet signed by two service providers will be sufficient for compliance with the requirement of this regulation. Therefore, the supply of signals can be commenced after signing of a term sheet. The detailed agreement can be signed later.

41. In order to curb the practice of oral interconnection agreements, the provisions of regulation 4.1 have also been amended to restrict the regulatory protection from disconnection without any notice to only those distributors of TV channels which have entered into written interconnection agreements.

42. However, considering the fact that sometimes signals are given to distributors of TV channels in compliance of orders of Courts of law, an exception has been made enabling the broadcasters/ distributors of TV channels (MSOs/ HTS operators) to give signals to distributors of TV channels (LCOs) without entering into written agreements.